



सत्साहित्य प्रकाशन

ग्राम-समाज का नया रूप

# स ह का रि ता

जवाहरलाल नेहरू

•

१९६४

सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली

प्रकाशक

मार्तण्ड उपाध्याय

मन्त्री, सस्ता साहित्य मण्डल,

नई दिल्ली

---

---

पहली बार : १९६४

मूल्य

दो रुपये

---

---

मुद्रक

सत्यप्रकाश गुप्ता

नवीन प्रेस, दिल्ली

## प्रकाशकीय

इस पुस्तक में श्री जवाहरलाल नेहरू के उन भाषणों का संग्रह किया गया है, जो उन्होंने सन् १९५८ से लेकर सन् १९६२ के बीच सहकारिता के बारे में दिए थे। भारत गांवों का देश है और हमारी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा खेती-बारी पर निर्भर करता है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे यहाँ खेती आज भी उसी तरह होती है, जिस तरह पुराने जमाने में हुआ करती थी।

इसमें सन्देह नहीं कि यदि हमें युग की रफ्तार के साथ चलना है और अपने देश में समाजवादी समाज की स्थापना करनी है तो हमें अपनी खेती की पद्धति को बदलना होगा। उसकी बुनियाद सहकारिता पर रखनी होगी।

कांग्रेस और सरकार दोनों ने कृषि की इस पद्धति को अपनाने पर जोर दिया है। नेहरूजी ने भी अपने इन भाषणों में इस बात पर प्रकाश डाला है। कृषि की सहकारी पद्धति के लाभों की उन्होंने विस्तार से चर्चा की है, लोगों की शकाओं का समाधान किया है और अन्त में बताया है कि हम अपने लक्ष्य की पूर्ति बिना इसके नहीं कर सकते।

सहकारी पद्धति के अनुसार काम आरम्भ हो गया है और पिछले कुछ वर्षों में इस काम में काफी प्रगति भी हुई है। जरूरी है कि यह प्रगति और तेज हो और यह तभी संभव हो सकता है जबकि लोग इस विषय को अच्छी तरह से समझें और इसे आगे बढ़ाने में पूरी तरह से सहायक हों।

यह पुस्तक इस दिशा का बड़ा ही उपयोगी प्रकाशन है।

इसी क्रम में दूसरी पुस्तक शीघ्र ही निकल रही है, जिसमें पंचायती राज की विशेषताएँ बताई गई हैं और पंचायतों का जाल सारे देश में फैलाने की अपील की गई है।

जो लोग खेती-बारी के काम में लगे हैं, उनके लिए तो यह पुस्तक

उपयोगी है ही, उनके लिए भी लाभदायक है, जो इस काम में रुचि रखते हैं ।

हमें आशा है, यह पुस्तक ग्रामीण तथा शहरी, दोनों क्षेत्रों में चाव से पढ़ी जायगी और सभी लोगों को इसके अध्ययन से लाभ होगा ।

—मन्त्री

## विषय-सूची

१ सहकारिता की कल्पना	६
२ "ग्रामीणों में मेरी श्रद्धा है ?"	२४
३ हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा	२८
४. न अवानक, न थोपा हुआ	३१
५. तात्कालिक लक्ष्य	३६
६. सहमति से आगे बढ़ेंगे	३६
७. दलगत राजनीति से अलग	४६
८. सामूहिक खेती का हीमा	५१
९. ग्राम-समाज का नया रूप	५८
१०. बुनियादी बातें	७२
११. समस्याओं पर लचीला दृष्टिकोण	७४
१२. सहकारी संगठन के व्यावहारिक पहलू	८३
१३. अधिक अन्न-उत्पादन—एकमात्र कसौटी	८२
१४. कमजोर याददाश्त	८५
१५. एकमात्र दृष्टिकोण	८८
१६. सहकारी खेती	८६
१७. आपसी आदान-प्रदान का तरीका	१०१
१८. अनुभव से सीखना	११०
१९. सेवा सहकारी समितियाँ	११३





सहकारिता





: १ :

## सहकारिता की कल्पना

बहुत बरसों से सहकारी आन्दोलन की पूरी विचार-धारा ने मुझे अपनी तरफ खींचा है। हालांकि निजी तौर पर मैं उससे सम्बन्धित नहीं था, किन्तु मैं उसके दर्शन, सामाजिक उद्देश्य और उस तौर-तरीके से आकर्षित हुआ था, जो विभिन्न उग्र कार्य-प्रणालियों के बीच से, जिन्हें मैं पूरी तरह से पसन्द नहीं करता, रास्ता बनाते हैं। हम बहुत सालों तक इस देश में आजादी की लड़ाई लड़ते रहे। शुरू में हमारा खास मकसद राजनैतिक आजादी था, लेकिन जैसे-जैसे आजादी की लड़ाई आगे बढ़ी, यह साफ हो गया कि सिर्फ राजनैतिक आजादी ही काफी नहीं होगी। उसमें सामाजिक उद्देश्यों को भी शामिल करना होगा। हमें आर्थिक आजादी भी हासिल करनी होगी।

उसूली क्षेत्र में बड़े-बड़े वाद और आन्दोलन चले हैं और मैं यहाँ उनका जिक्र नहीं करूँगा। पर एक बात को ज्यादा-तर लोगो ने बराबर मंजूर किया है। वह यह कि आज के हालात में महज खुदगर्ज यानी अपनी ही इच्छाओं को पूरा करनेवाला समाज मुनासिव नहीं है। इसलिए राज्य ने

समाज में अपना ही मतलब देखनेवाली प्रवृत्तियों पर अकुश लगाना शुरू किया। आज का हरेक राज्य, भले ही उसकी आर्थिक नीतियाँ कुछ भी हों, इन विषयों में न सिर्फ सीधी दिलचस्पी लेता है, बल्कि मतलबी प्रवृत्तियों पर रोक भी लगाता है। वह सबको एक-सा मौका देने की कोशिश करता है—पूरे अर्थ में नहीं, बल्कि मोटे तौर पर वह जुदा-जुदा समुदायों के बीच की भारी विषमताओं को कम करता है। ऐसा करने के लिए लाजिमी तौर पर राज्य को दखलन्दाजी करनी होती है। मुमकिन है, कभी-कभी यह दखलन्दाजी, कुछ लोगों की राय में, जरूरत से ज्यादा हुई हो और इन्सान की आजादी पर कुछ ज्यादा रोक लग गई हो, लेकिन अगर हम निजी आजादी को मूल्यवान समझते हैं, और हममें से बहुत लोग ऐसा समझते हैं, तो सवाल यह उठता है कि किस तरह निजी स्वतन्त्रता की रक्षा करते हुए हम अपने को एक खुदगर्जी समाज के शिकजे से बाहर रख सकते हैं—दोनों के बीच सम-तोल कायम कर सकते हैं? सहकारी आन्दोलन ऐसा दर्शन, ऐसी कार्य-विधि पेश करता है, जिसके जरिये ऐसी समाज-व्यवस्था स्थापित की जा सकती है।

स्वभावतः हममें से बहुत लोगों को इस विचार ने आकर्षित किया है। कई साल पहले, मेरे खयाल से एक-चौथाई सदी या इससे भी पहले, हमारी महान् राष्ट्रीय सस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश में कापरेटिव कामनवेल्थ यानी सहकारी समाज कायम करने का मकसद स्वीकार किया था। हमसे अक्सर पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या है और उसकी व्याख्या करना खासतौर से आसान नहीं था। जरूरी तौर पर मैं

उसके आम उद्देश्यों और सामान्य विचार-धारा के खीरे से बहुत-कुछ कह सकता हूं, किन्तु उसकी ठीक व्याख्या करना कुछ मुश्किल है। इसका यह मतलब नहीं कि यह विचार कुछ कमजोर है। असल में इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि यह विचार ऐसा कड़ा नहीं है, जिसे किसी व्याख्या के चौखटे में बन्द किया जा सके। इस सबके बावजूद यह एक अच्छा विचार है।

मैंने यह बताने के लिए यह जिक्र किया है कि किस तरह खुद राज्य के संगठन की कल्पना करते समय हमारा ध्यान सहकारी सिद्धान्त की ओर आकर्षित हुआ और हमने उसके विषय में पिछले कुछ सालों में ही नहीं, बल्कि कोई २० या ३० सालों या उससे भी पहले से सोचा-विचारा है। हमें ऐसे सामाजिक आदर्श की तलाश थी, जो हमारी जुदा-जुदा आकाक्षाओं को पूरा कर सके और उस तलाश ने हमें सहकारिता तक पहुंचाया। अवश्य ही, हमारी मूल इच्छा राजनैतिक स्वतन्त्रता की इच्छा थी। दूसरी इच्छा सामाजिक प्रगति और सामाजिक समानता की, लोगों को अवसर की समानता मुयत्सर कराने और उस समानता के रास्ते में आने-वाले वर्ग और जात-पात के भेदों को दूर करने की थी। आपको याद होगा कि हमारे आन्दोलन, विचार-धारा और कामों की बुनियाद में यह भावना हमेशा रही है। हमने यह सब गान्तिपूर्ण ढंग से करने की कोशिश की। असल में, हमने इससे भी ज्यादा असरकारक शब्दों का प्रयोग किया कि हम 'अहिंसक तरीके' से ऐसा करेंगे।

## सहकारी विचार का विकास

बहुत-से देशों ने काम के अलग-अलग दर्शनों का विकास किया है और कई तरह से उनमें समानता है, लेकिन किसी और देश ने आज तक क्रांतिकारी उद्देश्यों को हासिल करने तक के लिए शान्तिपूर्ण तरीके पर जोर नहीं दिया। आप जानते हैं, हमने महात्मा गांधी की प्रेरणा से ऐसा करने की कोशिश की और हमें इसमें राजनैतिक क्षेत्र में बड़ी हद तक और सामाजिक क्षेत्र में कुछ हद तक सफलता मिली। इन जुदा-जुदा खाहिशों ने हमें धीमे-धीमे सहकारी आन्दोलन के जरिये सहकारी ढंग से काम करने को उकसाया और हम सोचते हैं कि अखीर में यह तरीका सारे देश पर और लोगों के जीवन पर छा जायगा। यही वजह है कि हमने आज से कोई चौथाई सदी पहले कांग्रेस सविधान की धारा १ में उसको शामिल किया। इसके बाद हमें आजादी मिली और हमारी सविधान सभा ने देश का सविधान बनाया। सविधान में 'कापरेटिव कामनवेल्थ' (सहकारी राष्ट्र) शब्द तो नहीं आया है, क्योंकि मेरे खयाल से इस तरह के कानून के लिए वह शब्द कुछ बहुत साफ नहीं था। लेकिन राज्य-नीति के निर्देशक सिद्धान्तों और सविधान की भूमिका में यह बताया गया है कि सामाजिक नीति के क्षेत्र में हमारा क्या मकसद है। उस मकसद को हम अपने जुदा-जुदा कामों में सहकारी ढंग दाखिल करके हासिल करना चाहते हैं।

असल में, इसके अलावा मुझे ठीक ढंग से काम करने का और कोई तरीका नजर नहीं आता। एक ओर हमें भारी उद्योगों, बड़े उद्योगों का विकास करना है, क्योंकि हम भारी

उद्योगों को बुनियाद के बिना देश का उद्योगीकरण नहीं कर सकते। हम देश में औद्योगिक क्रान्ति करने के लिए तुले हैं। हम मौजूदा पीढ़ी के जमाने में वह सब हासिल कर लेना चाहते हैं, जिसे हासिल करने में और देशों को कहीं ज्यादा समय लगा है। यही नहीं, हम और भी बड़ी क्रान्ति, यह आणविक क्रान्ति, अणु-युग की क्रान्ति, करना चाहते हैं। हम यह भी चाहते हैं और हम यह उम्मीद करते हैं कि हम यह क्रान्ति अपने ही तरीके से, शान्तिमय और लोकतन्त्री तरीके से, कर सकेंगे और ऐसे कुछ आदर्शों को भी जिन्दा रख सकेंगे, जिन्होंने गुजरे जमाने में युगों-युगों तक भारत के लोगों को प्रेरित किया है। मैं लोगों के गये-गुजरे रिवाजों का जिक्र नहीं करता। मैं उन बहुत-सी प्रथाओं का भी जिक्र नहीं करता, जिन्होंने पिछले सैकड़ों और हजारों सालों के दौरान में हमें घेर लिया है। मेरा मतलब कुछ बुनियादी आदर्शों से है, जो, मैं मानता हूँ कि हमारे इतिहास के लम्बे जमाने में जाहिर रहे हैं।

हमारे पास और उपाय क्या है ? क्या राज्य सबकुछ हड़प ले ? जमीन की बात करें तो आप निजी निलकियत में बड़े कृषि-फार्म नहीं बना सकते । जाहिर है कि यह मुमकिन नहीं है । तब दूसरा रास्ता क्या है ? सहकारी तरीका अपनाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है । वस्तु, उसके द्वारा ही आप आदमियों या जमातों की बड़ी जायदादे बनना रोक सकते हैं और बड़ी इकाइयों से मिलनेवाला फायदा भी हासिल कर सकते हैं, और ऐसी इकाइयां आधुनिक विज्ञान और तकनीकी शास्त्र के प्रयोग के लिए बहुत जरूरी हैं । इस तरह सहकारी कोशिश छोटी इकाइयों और आधुनिक तकनीकी शास्त्र के बीच की खाई को पाटती है । यह गुजरे जमाने की तरह ही मौजूदा जमाने में भी महत्वपूर्ण बन गई है । सच पूछा जाय तो आज के भारत में वह और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि हम सचेत होकर, जान-बूझकर, एक निश्चित लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं ।

## गलत दिशा

इसमें गलत नहीं कि सहकारी आन्दोलन एक सर्जीव और गतिशील आन्दोलन है और उसकी अपनी समस्याएँ हैं । आपके अध्यक्ष ने उनका जिक्र किया है—यानी इस आन्दोलन में राज्य की दखलान्दाजी या उसके साथ उसके सम्बन्धों की समस्या है । आपकी वार्षिक रिपोर्ट में उन अहम फैसलों का जिक्र है, जो तीन साल पहले किये गए थे, जब कि ग्राम ऋण सर्वेक्षण समिति नियुक्त की गई थी । समिति ने सरकार को जो रिपोर्ट दी थी, उसमें उसने यह सिफारिश

की थी कि सरकार को सहकारी आन्दोलन को प्राणवान बनाने के लिए आर्थिक और अन्य प्रकार से उसके साथ अपना सम्बन्ध ज्यादा गहरा करना चाहिए। उसके बाद समिति के उससे सम्बन्ध रखनेवाले प्रस्तावों को सरकार ने मोटे तौर पर मंजूर कर लिया और उनपर बराबर अमल किया जा रहा है। अब मैं आपके सामने एक हकीकत मंजूर करना चाहता हूँ। मेरा खयाल है कि सरकार ने ग्राम ऋण सर्वेक्षण समिति के कुछ फैसलों को मानकर बहुत अच्छा नहीं किया। मुझे इसका अफसोस है। उसके लिए दूसरों की तरह मैं भी उतना ही जिम्मेदार हूँ। जितना ही मैंने इस बारे में सोचा है, उतना ही मैंने महसूस किया है कि कुछ मामलों में ग्राम ऋण सर्वेक्षण समिति का दृष्टिकोण सही नहीं था और वह देश के सहकारी आन्दोलन को गलत दिशा में धकेलने में सहायक हुआ।

यह गलत दिशा क्या थी? समिति ने हमारे लोगों को अविश्वास की निगाह से देखने की कोशिश की। उसने सोचा कि उनमें योग्यता की कमी है और वे खुद किसी काम को नहीं कर सकते, इसलिए सरकारी अफसरों को मदद देने के लिए आगे आना चाहिए। सरकारी धन उनकी मदद करे। अगर सरकारी धन आयगा तो उसके पीछे सरकारी अफसर भी आयेंगे। चूंकि छोटी सहकारी संस्थाओं के पास काफी रुपया और कार्यक्षम तकनीकी कर्मचारी नहीं होते, इसलिए बड़े सहकारी संगठन होने चाहिए, जिनकी सरकार शुरुआत और मदद कर सके। अब मैं यह मानता हूँ कि यह दृष्टिकोण गलत था, भले ही उसके पक्ष में कुछ दलीलें



दी जा सके, और उसने हमारे सहकारी आन्दोलन को गलत दिशा दी। जबसे मैंने यह महसूस किया, मैं उसकी ओर ध्यान दिलाने की कोशिश करता आ रहा हूँ और यहाँ इस मौके पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस दृष्टिकोण से भले ही कुछ स्थानीय और अस्थायी नतीजे हासिल किये जा सकें, वह सहकारी आन्दोलन को ऐसी दिशा में धकेलता है, जो सहकारी कतई नहीं है और इस आन्दोलन के अबतक के विकसित तत्व-दर्शन का निषेध करता है। अगर सहकारी आन्दोलन को सरकार द्वारा प्रेरित आन्दोलन होना है और सरकारी अफसरों को उसे चलाना है, तो उससे कुछ फायदा हो सकता है—बशर्ते कि सरकारी अफसर कार्यक्षम हों, किन्तु उससे इस अर्थ में बेहद नुकसान होगा कि लोगों को खुद अपना काम आप करने, स्वावलम्बन और आत्म-निर्भरता की भावना का विकास करने और वे गलती करना चाहें तो गलती करने के भी कम मौके मिलेंगे।

## सहकारी संस्थाओं का आकार

दूसरा सवाल यह है कि सहकारी संस्थाओं का आकार क्या हो? यह प्रवृत्ति दिखाई देती है कि छोटी सहकारी संस्थाओं को खत्म करके उनके स्थान पर बड़े सगठन खड़े किये जाय। मेरा खयाल है कि इस प्रवृत्ति को ग्राम ऋण सर्वेक्षण समिति की रिपोर्ट की दलीलों से बल मिला है। दलील यह है कि बड़े सहकारी सगठनों के पास अधिक साधन होंगे और वे प्रशिक्षित कर्मचारी नियुक्त कर सकेंगे और इस प्रकार ज्यादा अच्छा काम कर सकेंगे। मैं मानता हूँ कि इस दलील

मे कुछ वजन है, किन्तु ये अस्थायी नतीजे हासिल करने में हम शायद स्थायी हानि कर बैठेंगे। इस प्रकार का दृष्टिकोण स्वावलम्बन और आत्मनिर्भरता की भावना के विकास और आपसी सहयोग के रास्ते में बाधक होगा और हर बात के लिए सरकार का मुँह ताकने की आदत को बढ़ावा देगा, जिसे मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ और जो इस देश में बहुत ज्यादा चालू है।

आप जानते हैं कि मैं इस सरकार का हिस्सा हूँ। इसके बावजूद मैं महसूस करता हूँ कि वह नीति नामुनासिव है, जो लोगों को हर मौके पर सरकार का मुँह ताकने को बढ़ावा देती है, क्योंकि हम देश में स्वावलम्बन और आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना चाहते हैं। बेशक, सरकार को मदद देनी चाहिए, किन्तु मदद देना एक बात है और हुक्म चलाना दूसरी, और लाजमी तौर पर हुक्म चलाने की यह प्रवृत्ति ऊपर के स्तरों पर उतनी नहीं है, जितनी नीचे के स्तरों पर है। जितने नीचे आप जाइये, छोटा सरकारी कर्मचारी छोटा हाकिम नहीं, बल्कि बड़ा हाकिम दिखाई देगा। इसलिए मैं निश्चय के साथ कहना चाहूँगा कि यह प्रवृत्ति, जिसे ग्रान्ठन सर्वेक्षण समिति की रिपोर्ट ने बल दिया और जिसे बदकिस्मती से हमने सरकार की हैसियत से मजूर किया, एक बुरी प्रवृत्ति है। हमको जल्दी-से-जल्दी उससे पीछा छुड़ाना चाहिए, छोटी सहकारी संस्थाएँ बनाना चाहिए, और उनमें सरकारी दखलन्दाजी नहीं होनी चाहिए। हा, जहाँ मदद की जरूरत हो, जरूर दी जाय।

## छोटे सहकारी संगठन क्यों ?

सवाल है कि छोटे सहकारी संगठन क्यों ? उसके पक्ष में बहुत-से कारण हैं। संगठन जितना ही बड़ा होगा, उसके सदस्य एक-दूसरे को उतना ही कम जानेगे। अखीर में, वह ऐसा संगठन नहीं रहेगा, जिसमें लोग एक-दूसरे को नजदीक से जानते हैं और आपस में सहयोग कर सकते हैं। अवश्य ही, ऊँचे स्तर पर अगर लोग एक-दूसरे को न जाने तो उसका ज्यादा महत्व नहीं, लेकिन एक गाव के भीतर लोग एक-दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं और साथ मिलकर काम कर सकते हैं। इसलिए मैं छोटे सहकारी संगठनों, कमोबेश ग्राम स्तरीय सहकारी संगठनों का हामी हूँ। एक गाव के सहकारी संगठन में आस-पास के दो-तीन गाव और शामिल हो सकते हैं। बड़े संगठनों का फायदा हासिल करने के लिए बड़े क्षेत्र के छोटे संगठन अपना सघ बना सकते हैं, पर बुनियादी इकाई छोटी ही होनी चाहिए।

मैंने अक्सर कहा है और यहाँ फिर दोहराना चाहूँगा कि भारत की इमारत की नींव में तीन खम्भे होने चाहिए : (१) ग्राम पंचायत, (२) ग्राम सहकारिता और (३) ग्राम स्कूल। इन तीन खम्भों पर राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से भारत की इमारत खड़ी होनी चाहिए। आदतन हम ऊपर की बड़ी चीजों की बात सोचते हैं। ऊपर हमारी सर्वप्रभुता-सम्पन्न संसद है, जो कानून बनाती है और दूसरे तरीकों से देश की किस्मत का फैसला करती है। लेकिन संसद का तभी महत्व है, जब वह बुनियाद मजबूत हो, जिससे वह ताकत हासिल करती है। आप ऐम्प्ली संसद की कल्पना नहीं कर सकते, जो बिना किसी मजबूत बुनियाद के हवा में तैरती है

और आज भारत में वह बुनियाद गांव में है। इसलिए ग्राम पंचायत, ग्राम सहकारिता और ग्राम स्कूल का महत्व है।

## सहकारी खेती

मैं मानता हूँ कि सहकारी खेती के बारे में काफी बहस-मुबाहिता हुआ है। पहली बात यह है कि जब हम सहकारी आन्दोलन की बात करते हैं तो जाहिर है कि हम सिर्फ ऋण देनेवाली सहकारी संस्थाओं के बारे में नहीं सोचते। ये संस्थाएँ सहकारी आन्दोलन के मामूली अंग हैं, सहायक अंग हैं, लेकिन महत्वपूर्ण अंग नहीं हैं। सहकारी दर्शन की दृष्टि से वे महत्वपूर्ण नहीं हैं। जरूरी तौर पर ऋण देनेवाली सहकारी संस्थाएँ होनी चाहिए, पर हम चाहते हैं कि सहकारी कोशिशें नाना रूपों में विकसित हों, यथासम्भव अधिक-से-अधिक रूपों में, नहीं तो आप आधुनिक तकनीकी शास्त्र का फायदा नहीं उठा सकेंगे। जमीन और गृह उद्योगों की छोटी इकाइयों के पास विकास के साधन नहीं होते। उन्हें मिलकर काम करना होगा, वरना वे ज्यादा प्रगति नहीं कर सकती। इसलिए सहकारी प्रयास हर सम्भव दिशा में, छोटे भू-स्वामियों, कुटीर उद्योगों, उत्पादकों, उपभोक्ताओं आदि में फैलाना चाहिए। सबसे अखीर में मिली-जुली खेती की वारी आवेगी।

कभी-कभी दलील दी जाती है, “ओह, अगर आप मिली-जुली खेती को अपनायेंगे तो यह साम्यवाद होगा।” इसके उत्तर में यह कहने की इच्छा हो आती है, “वह कुछ भी हो, यह तर्क देनेवाले भाई में सोचने की ताकत का, बुद्धि का अभाव है।” हमें यह तय कर लेना चाहिए कि अगर कोई

चीज अच्छी है तो हम उसे जरूर हासिल करेंगे, फिर उसका कुछ भी नाम क्यों न हो। चीज की अच्छाई-बुराई पर वहस कीजिये, किन्तु यह कहना बिल्कुल बेहूदा है, “ओह, यह असाम्यवादी है अथवा साम्यवादी है और इसलिए हम उसे नहीं छुएँगे।” यह शीत युद्ध है और किसी समस्या पर विचार करते समय, चाहे वह आर्थिक हो या राजनैतिक, राष्ट्रीय हो अथवा अन्तर्राष्ट्रीय, मैं आशा करता हूँ, हम शीत युद्ध का सहारा नहीं लेंगे। यह भी याद रखना चाहिए कि हम सहकारिता अथवा और किसी भी बारे में जो भी कदम उठायेंगे, वह लोकनन्त्री चौखट में होगा यानी उसके लिए लोगों की सद्भावना हासिल करनी होगी। हम उन्हें मजबूर नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी सरकार अगले ही दिन उखड़ जायगी। हाँ, हम शासन को ही बदल दें, शासन की प्रणाली को ही बदल दें तो दूसरी बात है, किन्तु हमारा शासन अथवा शासन-प्रणाली को बदलने का कोई विचार या इच्छा नहीं है। इसलिए जो कुछ भी करना है, लोगों की सद्भावना और उनकी सहमति से करना होगा।

इस बुनियाद पर विचार करने पर मुझे जरा भी शक नहीं कि बहुसंख्यक उदाहरणों में सहकारी खेती मुनासिब है। फिलहाल मैं यह नहीं कहता कि हर मामले में वह उचित है, क्योंकि हालात जुदा-जुदा हैं। मिसाल के लिए यह हो सकता है कि धान पैदा करने के लिए एक तरह की खेती की जरूरत हो और गेहूँ पैदा करने के लिए दूसरी तरह की। इसे अलग रखकर जहाँ जमीन के छोटे टुकड़े हों, मेरे खयाल से उनको मिलाकर खेती करना काफी फायदेमन्द होगा। उन

टुकड़ों के मालिक अलग-अलग हो सकते हैं, किन्तु उनमें सामूहिक खेती हो सकती है। सिर्फ इसी तरह काफी बर्बादी को टाला जा सकता है और नाना रूपों में तरक्की की जा सकती है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसे आसानी से समझा जा सकता है।

हमें कृषिक्षेत्र में सहकारिता का व्यापक प्रसार करना होगा। वह आज सीमित है और इस दिशा में आखरी कदम लोगों की सहमति से सहकारी अथवा मिली-जुली खेती का होगा। हम नमूने के तौर पर राजकीय कृषि-फार्म कायम कर सकते हैं, जहां मिली-जुली खेती की जाय। उनसे लोगों को पता चलेगा कि मिली-जुली खेती कितनी फायदे की है।

इस तरह वे और हम इन प्रयोगों से सीख सकेंगे। मैं किसान नहीं हूँ। मुझे कहना पड़े तो कहूंगा कि मैं केवल उसूल की चर्चा कर सकता हूँ। पर इस बारे में सोचने और लोगों के साथ चर्चा करने से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि मौजूदा हालात में हमको देश के अधिकतर भाग में सहकारी खेती की ओर बढ़ना होगा।

भारत में हम भारी काम में जुटे हैं और उससे तीसरी योजना को पूरा करने में मदद मिलेगी। दूसरी पंचसाला योजना हमारी लम्बी चढ़ाई की एक छोटी मंजिल है। हमको एक-एक कदम ऊंचा और ज्यादा ऊंचा चढ़ना होगा। यह महान काम है, क्योंकि हम दसियों साल के प्रयास और कठिन काम को कहीं थोड़े समय में पूरा करना चाहते हैं और लोक-तन्त्री तरीके से करना चाहते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं और हम अपनी ताकत के हिसाब से कोशिश करते रहेंगे।

इस बीच और बातें भी हो रही हैं। तकनीक शास्त्र आवर्च्यजनक गति से बदल रहा है। विज्ञान गैर-मामूली रफ्तार से नई ताकत हमारे हाथों में सौंप रहा है। कुछ हद तक हमें इन घटनाओं के आगे रहना होगा। खेती को ही लीजिये। यह भी सोचिये कि अणु-शक्ति का किसी-न-किसी रूप में, आइसोटोपों की शक्ल में, खेती में उपयोग किया जा रहा है। इससे उत्पादन में बड़ा अन्तर आ रहा है। जाहिर है कि हमें अपने घेरो से बाहर निकलना होगा। अगर आप गरीब किसान को अपने ही साधनों पर छोड़ देंगे तो आप ऐसा नहीं कर सकेंगे। विचारा गरीब किसान अकेला क्या कर सकता है? इसलिए आपको किसी-न-किसी आन्दोलन का सहारा लेना होगा। यह इसलिए भी जरूरी है कि बड़े जमींदारों और ताल्लुकेदारों वगैरा का हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है। हमने इन वर्गों को करीब-करीब खत्म कर दिया है। इसलिए हमारे सामने सहकारी आन्दोलन का ही एक रास्ता है। सहकारिता के जरिये ही व्यक्ति, छोटा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की, अपनी आजादी की, रक्षा कर सकता है और साथ ही बड़े पैमाने पर काम कर सकता है तथा विज्ञान और तकनीक शास्त्र का फायदा उठा सकता है।

अखीर में एक बात और। आपको हमारे सामुदायिक विकास आन्दोलन, विकास-खण्डों और राष्ट्रीय विस्तार सेवा की जानकारी है। उसकी आसानी से आलोचना की जा सकती है और यह कहा जा सकता है कि बहुत-से स्थानों में आगा के अनुरूप नतीजा नहीं आया। फिर भी, यह एक उल्लेखनीय आन्दोलन है, महज भारत में ही नहीं। पिछले

पाच सालो या इससे कुछ ज्यादा समय मे इस आन्दोलन ने भारत मे जो कुछ हासिल किया है, उसे मै आश्चर्यजनक मानता हूं। मै फिर कहता हूँ, उसमे कमजोरियां है और यह सब स्वाभाविक है, लेकिन इस आन्दोलन का भारत के भविष्य पर, खास तौर पर देहाती भारत के भविष्य पर, बड़ी हद तक असर पड़ेगा। वह अभी भी असर डाल रहा है। मै चाहता हूँ कि सहकारी आन्दोलन ज्यादा-से-ज्यादा फैले और इसलिए मै चाहता हूँ कि उसके और इन सामुदायिक विकास-योजनाओ और विकास-खण्डों के बीच नजदीक का तालमेल हो। मै खुद नही जानता कि यह तालमेल क्या शकल अखितयार कर लेगा, लेकिन देश के इन दोनो महत्वपूर्ण आन्दोलनो को, जो नीव से निर्माण कर रहे है, कदम-से-कदम मिलाकर चलना होगा।<sup>१</sup>

---

१. भारतीय सहकारी कांग्रेस, नई दिल्ली मे १२ अप्रैल १९५८ को दिया गया भाषण।



## “ग्रामीणों में मेरी श्रद्धा है”

मैं आपको बताऊंगा कि हममें कई लोग कृषि-सुधार के इस मामले में क्या महसूस करते रहे हैं। हमने जुदा-जुदा उपायों पर अलग-अलग सोचा है। एक सवाल जमीन की मालिकी की ज्यादा-से-ज्यादा हद तय करने का है और दूसरा सवाल खेती की सहकारी समितियों का है। हम अब यह महसूस करने लगे हैं कि ये दोनों सवाल एक-दूसरे से बहुत ही जुड़े हुए हैं। अगर भारत में दूसरे कुछ देशों की भांति बड़े कृषि-फार्म हो तो आप इससे सहमत हो या नहीं, यह सोचा जा सकता है कि वे व्यवस्थित रूप से काम करेंगे, काफी ज्यादा उत्पादन करेंगे और आधुनिक तरीकों का उपयोग कर सकेंगे। भारत की बुनियादी समस्या यह है कि उसमें जमीन की इकाइया बहुत छोटी हैं—मामूली तौर पर मैं कहूँ कि उनका क्षेत्र एक, दो या तीन एकड़ है। इन छोटी इकाइयों में किसान सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि जैसे-तैसे खेती करते रहे और आधुनिक तरीके इस्तेमाल करने में ज्यादा तरक्की नहीं कर सकते। मालिकी की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का यह मतलब होगा कि कुछ

बड़े फार्म छोटे टुकड़ों में बांटने होंगे । इस सुधार का मंशा यही है और ऐसा होना ही चाहिए । लेकिन अगर आप तरक्की करना चाहते हैं और आधुनिक तरीके अपनाना चाहते हैं तो जमीन के उन छोटे-छोटे टुकड़ों में सहकारी खेती की जानी चाहिए, ताकि उन्हें आधुनिक तरीकों का फायदा मिल सके ।

जब मैं सहकारी खेती की बात करता हूँ तो मेरा मतलब यह है कि सहकार कई तरह का हो सकता है । ऋण देने-वाली सहकारी समितियाँ तो हैं ही । हमारे खयाल से पहला कदम ऐसी सहकारी समितियों की स्थापना होना चाहिए, जो बीजों को जैने बीज, नाद वगैरा खरीदने का काम करें । वे किसानों के लिए जुदा-जुदा सेवाएँ दे सकती हैं । अगला कदम धीमे-धीमे विचौलियों को हटाने का हो सकता है । फिर अगले कदम की दारी आदमी और वह मिनीजुली खेती का कदम हो सकता है, भले ही उनमें अपनी-अपनी जमीनों पर किसानों का मालिकी हूँ कायम रहे । यह दृष्टिकोण है और मालिकी की अधिकतम सीमा तय करने का यह सवाल ग्राहगी समूहों के निर्माण के सवाल के साथ अधिक-से-

सहकारी समिति हो और उन्हें फैसले करने की सत्ता और अधिकार दिये जाय । वे गलतियाँ कर सकती हैं और उन्हें गलतियाँ करने का भी हक होना चाहिए । हम जोखिम उठाते हैं । उनकी सत्ता पर अकुश लगाने और उन्हें वेबस महसूस कराने के बजाय जोखिम उठाना ज्यादा अच्छा है । जहातक मेरा खुद का ताल्लुक है, देहाती लोगो की जन्मजात समझ-दारी मे मेरी काफी श्रद्धा है । बेशक वे गलतियाँ करेंगे । इसका महत्व नहीं । हम सब गलतियाँ करते हैं । लेकिन अगर आप उनमे यह भावना पैदा करते हैं तो उनमे आत्म-निर्भरता आयगी, वे पहल करेंगे, खुद काम करने लगेंगे और सरकारी अफसरों का इन्तजार नहीं करेंगे कि वे आये और उनका काम करें ।

मैं फिर कहता हूँ कि सहकारी संस्था, जिसकी हम कल्पना करते हैं, छोटी होगी, ताकि उसके सदस्यों में निकटता हो और एक दूसरे की जानकारी हो । वह उनसे परे की चीज नहीं होगी । अगर सहकारी समिति के सदस्यों को यह पता हो कि उनके गाँव में कौन भला आदमी है और कौन बुरा, तो शायद वह समिति ज्यादा कामयाब होगी, बजाय इसके कि कानून की कोई पेचीदा तरकीब हो या कुछ ऐसे बड़े अफसरों का हाथ हो, जो स्थानीय हालात से बिल्कुल नावाकिफ हो ।

आमतौर पर यह कहा जा सकता है कि ग्राम-पंचायतों या ग्राम सहकारी समितियों में दलबन्दी की राजनीति ज्यादा नहीं होती और मेरे खयाल से उसे बढ़ावा भी नहीं दिया जाना चाहिए । उनकी बुनियाद ही जुदा है । बड़े शहरों के कारपोरेशनों (निगमों) और म्युनिसिपैलिटियों (नगर-



: ३ :

## हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा

हमें यह याद रखना होगा कि भारत में आबादी के हिसाब से कितनी जमीन है। इस अनुपात पर बहुत-कुछ मुनहसिर करता है। आमतौर पर हमारे यहाँ जमीन की इकाइया बहुत छोटी है। जिन्हे जमीन की जरूरत है, अगर उनमें हम जमीन का बटवारा करने लगे तो ये इकाइया और भी छोटी हो जायगी। जमीन की इस बहुत ही छोटी इकाई में, जो अक्सर फायदे की नहीं होती, आप प्रगतिशील तरीके अपनाये जाने की उम्मीद नहीं कर सकते। फिर करना क्या होगा ? मुझे लगता है कि एक ही रास्ता है और वह है सहकारी प्रयास। लाजिमी तौर पर राज्य की उसमें मदद होनी चाहिए। लेकिन मैं अपने बहुत-से लोगों की यह आदत छुड़ाना चाहता हूँ, जो ब्रिटिश शासन-काल में पैदा हुई है, कि कोई दूसरा आकर उनका काम कर दे। मैं चाहता हूँ कि सहकारी समिति किसानों की सहकारी समिति हो, किसानों पर लादी गई और सरकारी अफसरों के जरिये चलाई जानेवाली राजकीय सहकारी समिति नहीं। मैं सरकारी अफसर नहीं चाहता। अफसरों से मेरा बहुत सावका पड़ता है और इसलिए नहीं

चाहता कि वे सरकारी मशीन को लेकर देशभर में फैल जाय और इस तरह किसान की काम करने की पहल को कमजोर कर दे । मेरे खयाल से एक ही रास्ता है, कि हमारे किसानों में सहकारी भावना का विकास किया जाय, क्योंकि सच्चे सहयोग से ही छोटे सहकारी संगठन खड़े हो सकेंगे । एक गांव के लिए या दो-तीन गांवों के लिए एक सहकारी संगठन होना चाहिए । मुद्दा यह है कि सहकारी संस्था के सदस्य आपस में एक-दूसरे को जाननेवाले होने चाहिए ।

कुछ लोग दलील देते हैं कि छोटी सहकारी संस्थाओं के साधन कम होंगे । यह सही है और इसका एकमात्र उपाय यह है कि छोटी सहकारी समितियों का एक बड़ा संघ बना दिया जाय । उसका सहकारी संघ या और कोई नाम रखा जा सकता है और वह अपनी शाखाओं को खास सलाह और सहायता देगा । आप जानते हैं कि इन्सानो से सम्बन्ध रखने-वाली समस्या मुश्किल होती है । जब बड़ी तादाद में इन्सान इकट्ठे होते हैं तो समस्या और भी मुश्किल हो जाती है । खेती में हमको सिर्फ मर्द और औरतो से ही नहीं, बल्कि जानवरों और पौधों से भी निपटना होगा । उनके बीच कुछ तालमेल रखना होगा । जहां थोड़ा भी असंतुलन हुआ कि सारा ढाँचा गड़बड़ा जाता है और योजना नाकामयाब हो जाती है ।

बेशक, इन सब कठिनाइयों का सामना किया जाता है और उनपर काबू किया जाता है, लेकिन तरक्की आशा से धीमी होती है और कभी-कभी सामने मायूसी भी आ खड़ी होती है । हम क्यों न तेजी से आगे बढ़ें ? पर हमें याद रखना है कि हम कूच कर रहे हैं । हम अकेले या छोटे समूहों में कूच

नहीं कर रहै है, हमारी ३६ करोड़ की बिरादरी है और हम सब कूच कर रहे हैं। हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा और हम एक-दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। हमें इस प्रयास में एक-दूसरे की मदद करनी होगी। मैं यह मानता हूँ कि शुरू की कठिनाई पार करने के बाद प्रगति की रफ्तार तेज होगी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा है, मुझे अपने लोगो की और अपने किसानों की समझदारी और बुद्धिमानी में भारी श्रद्धा है।<sup>१</sup>

---

१ १४ नवम्बर, १९५८ के 'कुरुक्षेत्र' के एक लेख से।

## न अचानक, न थोपा हुआ

नागपुर-कांग्रेस ने दो प्रस्ताव स्वीकार किये। एक योजना के बारे में यानी तीसरी पांचसाला योजना के बारे में और दूसरा कृषि और भूमि-सुधारों के बारे में। इससे कई महीने पहले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई और उसने विशेष समितियाँ कायम की—एक योजना के बारे में और दूसरी कृषि और सम्बन्धित विषयों के बारे में। दोनों ही ऊँचे स्तर की समितियाँ थीं। उनकी रोज-ब-रोज बैठकें हुईं। कांग्रेस से बाहर के खास आदमियों—अर्थशास्त्रियों और दूसरों को उन समितियों ने बुलाया और उन्होंने हर नजरिये से पूरी तरह विचार किया। जुदा-जुदा अर्चाओं, बातचीतों, कांग्रेस संगठन से जारी की गई प्रश्नावलियों और उनके उत्तरों के आधार पर यह विचार हुआ। पिछले दो या तीन सालों से—हम इन विषयों पर, कृषि, भूमि-सुधारों और जमीन की मालिकी की ज्यादा-से-ज्यादा हद तक करने के बारे में विचार करते आ रहे थे।

मिसाल के तौर पर जमीन की मालिकी की अधिकतम सीमा का सबाल ही लीजिये। साल-दर-साल इसपर विचार



किया गया और इसलिए नागपुर कांग्रेस अधिवेशन के सामने यह सवाल कोई अचानक उपस्थित नहीं हो गया। इसपर कांग्रेस कमेटी की बैठको में सालो विचार हुआ। फिर हमने दो समितियाँ कायम की, जिन्होंने नागपुर कांग्रेस अधिवेशन के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है। इस तरह यह सवाल आया और हमने उसपर अपनी दूसरी कमेटियों में—कांग्रेस कार्यसमिति और विषय समिति में विस्तार से विचार किया और उनकी सिफारिशों को मुख्य रूप से स्वीकार किया।

इसलिए अगर कोई यह कहता है कि मैंने दूसरों पर सही या गलत कोई चीज थोपी है तो यह मुनासिब या तथ्यों के मुताबिक नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि मेरा इन सुधारों पर गहरा विश्वास है। 'गहरे' गन्द का इस्तेमाल मैं इसलिए करता हूँ कि भारत की तरक्की पर भी मेरा उतना ही गहरा विश्वास है। मैं राजनेता नहीं हूँ। मैं भारत में कुछ करना चाहता हूँ, अपनी जिन्दगी के बाकी सालों में भारत को बदल डालना चाहता हूँ, देश के किसानों को, कृषि को, अर्थ-व्यवस्था आदि को बदलना चाहता हूँ।

मैं गलती कर सकता हूँ, मैंने अक्सर गलतियाँ की हैं। लेकिन एक लक्ष्य पर पहुँचने की मेरी तीव्र अभिलाषा है। कुछ दिन पहले 'कुछ पुरानी चिट्ठियाँ' पुस्तक प्रकाशित हुई है और मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि पिछले ३० या ४० साल से मेरा क्या दृष्टिकोण रहा है, मैंने किन नीतियों की हिमायत की है। मैं यह नहीं कहता कि एक ही बात को

बार-बार दोहराना कोई बहुत अच्छी बात है। दुनिया बदल रही है और लोगों को भी अपनी राय अथवा विचार बदलना चाहिए और दुनिया के साथ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन यह सिर्फ यह बताने के लिए कहा है कि मैंने पिछले बहुत-से सालों से इसी तरह महसूस किया है। इन सालों में मैं अनेक तरीकों से कांग्रेस के सामने अपने विचार रखता आया हूँ। कभी-कभी मेरे विचारों को गांधीजी पसन्द नहीं करते थे। वह कहते थे, “तुम्हारी रफ्तार बहुत तेज है।”

इसलिए कांग्रेस ने जो कुछ किया है, वह पिछले २० सालों के सोच-विचार का नतीजा है। यह सही है या गलत, इसपर हम आगे विचार कर सकते हैं, लेकिन इसपर हमने लम्बा विचार और चिन्तन किया है।

## सेवा सहकारी समितियाँ

मैं यहाँ मिली-जुली खेती की बात नहीं करता, क्योंकि वह दूसरा सवाल है, पर सहकारिता कांग्रेस-दृष्टिकोण की बुनियाद रही है। हमने कांग्रेस के संविधान में ‘सहकारी समाज’ का जिक्र किया है। हम उद्योग के क्षेत्र में सहकारी प्रयास की बात करते हैं। हमने हमेशा इसकी चर्चा की है। हमने कांग्रेस के नागपुर-अधिवेशन में यह तय किया कि तीन साल के भीतर सारे देश में सेवा सहकारी समितियाँ कायम की जाय। ध्यान रखिये कि इस समय संयुक्त खेती की बात नहीं है, केवल सेवा सहकारी समितियों पर जोर है। दूसरे शब्दों में, लोग अपनी जमीन अपने अधिकार में रखते हुए, उसमें अलग खेती करते हुए, दूसरे और-और आर्थिक उद्देश्यों के लिए ग्राम सहकारी

समिति में शामिल हो सकते हैं। मैं यह कहूंगा कि इस लम्बी-चौड़ी दुनिया में कोई भी आदमी इस बात से असहमत नहीं हो सकता, वशर्ते कि वह आधुनिक दुनिया से विल्कुल अपरिचित न हो। यह प्रस्ताव इतना स्वयं-सिद्ध है कि उसे चुनींती नहीं दी जा सकती, खास तौर पर हिन्दुस्तान जैसे देश में, जहाँ जमीन की इकाइया इतनी छोटी है। अगर आप इन छोटी और अलग-अलग इकाइयों को ज्यों-की-त्यों रखते हैं और उन्हें सहकारी जमीन में नहीं बाँधते तो उनके मालिक हमेशा गरीबी और जड़ता के दलदल में फँसे रहेंगे। वे उससे कभी बाहर नहीं निकल सकेंगे। कड़ी मेहनत करके, सुधरे बीज काम में लेकर और इस तरह के उपायों के जरिये वे अपनी हालत में थोड़ा सुधार कर सकते हैं, लेकिन वे जैसे-तैसे पेट भरने की सतह से ऊँचे कभी नहीं उठ सकेंगे, सचमुच अपनी कोई तरक्की नहीं कर सकेंगे। इस स्थिति को कोई कैसे पसन्द कर सकता है? हमें इस घेरे को तोड़ना होगा। इसके लिए हमको बहुत-सी बातें करनी होंगी। उद्योगीकरण का और इन पाँचसाला योजनाओं का यही मकसद है, यानी कि लोग खेती से हटकर उद्योगों में लगे। उद्योगों से मेरा मतलब सभी तरह के उद्योगों से है। बड़े उद्योग, छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग सभी उनमें आ जाते हैं। लेकिन कृषि के क्षेत्र में, छोटी इकाइया तभी काम कर सकती है, जबकि सेवा सहकारी समितियाँ कायम होती हैं, और बीज, खाद और मशीनें वगैरा जुटाने का काम अपने हाथ में ले लेती हैं। केवल इसी तरह किसान सुधारों और आधुनिक तरीकों से फायदा उठा सकेगा।

कांग्रेस ने यही सेवा सहकारी समितियों की बात कही है।

यह पहला कदम है। यह भी कहा गया है कि आगे हमारा मकसद संयुक्त खेती है, पर उसके लिए सम्बन्धित लोगों की रजामन्दी आवश्यक होगी। इस प्रकार मोटे तौर पर हम तीन साल में सेवा सहकारी समितियों पर जोर देंगे। इस अरसे में अगर कोई आदमी या सहकारी समिति संयुक्त खेती की व्यवस्था करना चाहेगी तो वह ऐसा करने को आजाद होगी। इसके लिए कोई दबाव नहीं डाला जायगा। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना ताल्लुक है, मेरा विश्वास है कि संयुक्त खेती, खासकर हिन्दुस्तान के हालात में मुनासिब और लाभदायक चीज है।

इसलिए कांग्रेस ने केवल ग्राम सहकारी सगठन को मंजूर किया है और यह याद रखने की बात है कि योजना-आयोग एक या दो साल से इसकी हिमायत करता आ रहा है। कांग्रेस ने केवल इतना और जोड़ा है कि लोगों की रजामन्दी से संयुक्त खेती हमारा आखिरी मकसद है।

हमने कोई खास कानून नहीं बनाया। हमने महज यह सुझाया है कि मौजूदा कानूनों को व्यापक बनाया जाय ताकि सहकारी समितियाँ बनाने में आसानी हो जाय। मिसाल के लिए अभी वही लोग सहकारी समितियों में लिए जाते हैं, जिनके पास कुछ जायदाद या साधन होते हैं। यह बिल्कुल गलत है। हम गाँव के हर आदमी को सहकारी समिति में शामिल करना चाहते हैं, चाहे उसके पास साधन हो या न हों। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो अमीर लोग ही शामिल होंगे और साधनहीनों को आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं मिलेगा।<sup>१</sup>

१. नई दिल्ली में ७ फरवरी, १९५६ की प्रेस-कान्फ्रेंस के अंश।

## लात्कालिक लक्ष्य

देश के लिए अनाज की स्थिति से अधिक और कोई महत्वपूर्ण समस्या नहीं हो सकती, यह जाहिर है। मैं सदन को केवल यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी सरकार किसी भी समय खाद्य समस्या के बारे में अचेत नहीं रही। यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है और सिर्फ वही उसको नजरंदाज कर सकते हैं, जो अपने इर्द-गिर्द की घटनाओं से बिल्कुल बेखबर हो। इसका यह मतलब नहीं कि हमने जब-तब इस बारे में या तत्सम्बन्धी प्रबन्ध में गलती नहीं की है या कर नहीं सकते, लेकिन जैसा कि सदन को पता है, तीन बुरे साल गुजरे हैं और अब धान की अच्छी फसल आने और गेहूँ की अगली अच्छी फसल की सम्भावना के साथ हम नया मोड़ ले रहे हैं। हमने राजकीय व्यापार के सम्बन्ध में और कुछ दूसरी समस्याओं, जैसे कि सहकारी समितियों के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण फैसले किये हैं और मेरा खयाल है उनका आखिरकार खाद्य-समस्या और अनाज के वितरण के कार्य के साथ गहरा सम्बन्ध है।

## खाद्यान्नों का राजकीय व्यापार

जब हमने कहा कि हम थोक व्यापार को राज्य के हाथों में लेंगे तो हम इस विषय में पक्के थे और अखीर तक पक्के रहेगे। हमने फैसला तो कर लिया, लेकिन हमारे पास मशीनरी नहीं थी। इसलिए हमको लाजमी तौर पर लाइसेंस देने और कुछ थोक व्यापारियों को राज्य की ओर से काम करने का अधिकार देना पड़ा। यह कोई बहुत सन्तोषजनक प्रबन्ध नहीं है। हम सब थोक व्यापारियों पर आसानी से काबू नहीं कर सकते और यह जाहिर है कि उन्हें हमारी नीति में यह परिवर्तन पसन्द नहीं आया। जब आप किसी इंसान या समुदाय को एक नीति चलाने की जिम्मेदारी सौंपते हैं, जो उसकी अपनी नहीं है या उसके हित में नहीं है तो विलाशक कठिनाइयाँ उठ खड़ी होती हैं। पर इस समय हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर हम अपने सहकारी संगठनों का विकास कर लें, जैसा कि हम उम्मीद करते हैं तो ये कठिनाइयाँ कम होंगी और अन्वीर में बिल्कुल खत्म हो जायगी। इसलिए इस निगाह से और दूसरी निगाहों से भी यह जरूरी है कि हम गावों में और दूसरी जगह अपने सहकारी संगठन बढ़ाएँ।

संयुक्त खेती

का सघ हो । हमने यह भी कहा है कि हमारा मकसद सयुक्त खेती है और हम इसे किसानों की रजामन्दी और मजूरी से ही हासिल करना चाहते हैं । हम सेवा सहकारिता पर जोर देंगे और उसकी वजहें साफ हैं, जो व्यावहारिक भी हैं और दूसरी तरह की भी हैं । हमें यकीन है कि देश की आज की हालत में जमीन को छोटी इकाइयों के होते हुए बड़ी इकाइयों का निर्माण जरूरी है, ताकि उन्हें आधुनिक तरीकों, औजारों और साधनों का फायदा मिल सके । इसलिए निजी तौर पर मुझे यकीन है कि यह सही रास्ता है । अगर जमीन की हमारी इकाइया छोटी हैं तो खेती में हम ठोस प्रगति नहीं कर सकते और बड़ी इकाइयों के लिए या तो बड़े जमींदारों की जरूरत होगी या सहकारी सगठन बनाने होंगे । अगर हम बड़े जमींदार नहीं रहने दे सकते तो हमें लाजमी तौर पर सहकारी सगठनों का सहारा लेना होगा । हम उम्मीद करते हैं कि ये सेवा सहकारी समितियाँ देश-भर में फैलेगी और यहाँ-वहाँ सयुक्त खेती भी होगी तो उसके उदाहरण और नतीजे सयुक्त खेती के पक्ष में सबसे प्रबल तर्क सिद्ध होंगे । दरअसल सदन के सदस्यों को यह जानकर अचरज होगा कि आज भारत में कई सौ और शायद एक हजार से अधिक या करीब दो हजार सयुक्त कृषि-फार्म हैं । मेरे पास उनकी सफलता के आकड़े नहीं हैं । लेकिन मुझे पता है कि उनमें से कुछ काफी कामयाब हुए हैं । दरअसल, किसानों ने ही आकर मुझे उनके बारे में बताया है ।

: ६ :

## सहमति से आगे बढ़ेंगे

माननीय सदस्य श्री मसानी उत्तेजित-से क्यों हो गये ? कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन द्वारा स्वीकृत कुछ प्रस्तावों से वह भडक उठे हैं । उनमें एक प्रस्ताव भूमि-सुधार और सहकारी समितियों के सम्बन्ध में है । उन प्रस्तावों में यह कहा गया है कि हमारा उद्देश्य और लक्ष्य संयुक्त खेती है और लक्ष्य यह होते हुए भी हमें फिलहाल अगले तीन सालों में सेवा सहकारी संस्थानों पर जोर देना चाहिए । यह भी जोर देकर कहा गया है कि सहकारी प्रयास स्वाभाविक रूप से स्वेच्छा से होना चाहिए और यदि संयुक्त खेती आयगी तो यह सम्बन्धित लोगों की सहमति से ही आयगी । श्री मसानी का कहना है कि वह हमेशा ही सहकारी सिद्धान्त के पक्ष में रहे हैं, लेकिन कांग्रेस प्रस्ताव में उसका जिस रूप से जिक्र किया गया है, उसका सहकारिता से कोई वास्ता नहीं है, कारण ज्योंही संयुक्त खेती का विचार सामने आया कि वह सहकारी प्रयास नहीं रहेगा । उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी भी मजिल पर संयुक्त खेती होगी तो उसके फलस्वरूप लाजिमी तौर पर सामूहिकवाद का जन्म होगा । यह उनकी दलील है ।



सामूहिकवाद से वे हालात पैदा होंगे, जो उनकी राय से रूस, चीन और दूसरी जगहों पर मौजूद हैं। इसलिए यह फिसलन-भरा रास्ता है, जो रसातल को ले जानेवाला है। यह उनकी दलील है और मैं उम्मीद करता हूँ, मैंने उसे सही-सही पेश किया है।

इस दलील में बहुत-सी बातों को मान लिया गया है, जिनका वजूद ही नहीं है और इसलिए उसका जवाब देना अधिक मुश्किल नहीं है। वह यह मानकर चलते हैं कि जहाँ सयुक्त खेती होगी, वह सहकारी प्रयास नहीं रहेगा। मैंने सयुक्त खेती की कई आलोचनाएँ सुनी हैं, पर पहली बार मैंने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किये जाते सुना है। वह कहते हैं कि सयुक्त खेती होगी तो लाजिमी तौर पर उससे सामूहिक खेती का जन्म होगा। यह भी एक अजीब बात मालूम पड़ती है। मैं खुद मोटे तौर पर सामूहिक खेती के हक में नहीं हूँ। लेकिन मैं सहकारी प्रयास में विश्वास करता हूँ और मैं दृढ़ता से और पूरी तरह सयुक्त खेती के औचित्य को स्वीकार करता हूँ। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। मैं हर खेत पर और हर किसान के पास जाऊँगा और उसे इसे मजूर कर लेने को कहूँगा। अगर किसान इसे स्वीकार नहीं करते तो मैं उस पर अमल नहीं करा सकता। यह दूसरी बात है। मजूर उन्हें करना है। मैं यह नहीं कहता कि इस या और किसी दूसरी समस्या के बारे में दुनिया के हर देश में एक ही उसूल लागू किया जा सकता है। हम व्यवहार के लिए कुछ सामान्य सिद्धान्त स्वीकार कर सकते हैं, किन्तु हर देश की परिस्थितियों और तथ्यों की वास्तविकता की रोशनी में परीक्षा

करनी होगी और किसी दूसरे देश की ऐसी बात को हम अपने यहाँ नहीं थोप सकते, जो हमारे लिए मौजूद न हो। अगर मैं भारत के किसानों के लिए कोई बात पेश करता हूँ तो वह इसलिए कि मैं उसे यहाँ की परिस्थितियों में मुनासिब और फायदेमन्द समझता हूँ। मैं नहीं कह सकता कि बदलती हुई इस दुनिया में, मैं या ग़ौर कोई कुछ बरसों बाद क्या सोचेंगे, क्योंकि हम तेजी से बदलते युग में रह रहे हैं।

श्री मसानी कहते हैं कि वह काम के परम्परागत तरीके में कुछ भी हेर-फेर करने के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि वह पारिवारिक खेती, व्यक्तिगत खेती के परम्परागत तरीके को जारी रखना चाहते हैं। मैं खुद परम्परा के खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन हम देश में एक बात जरूर चाहते हैं कि लोग, जहातक सम्भव हो, परम्परा के बन्धनों से मुक्त हो। हमें परम्परा की काफी मात्रा मिल चुकी है और कुछ रूपों में हम परम्परावादी, कट्टर सिद्धांतवादी और इसी तरह के वादी बन गये हैं और मेरा श्री मसानी से चाहे जितना मतभेद हो, मैं यह नहीं मानता कि उस अर्थ में वह परम्परावादी अथवा कट्टर सिद्धान्तवादी है।

## लोगों की रजामन्दी

इसलिए हम इस सवाल पर उसके गुण-दोष की दृष्टि से विचार करें और यह समझें कि सहकारी क्षेत्र में हम जो कुछ करेंगे, उसके लिए सम्बन्धित लोगों की स्वेच्छिक सहमति जरूरी होगी, वरना मैं श्री मसानी की इस बात से सहमत होऊँगा कि वह सहकार नहीं होगा, और कुछ होगा। अगर

हम यह मान ले तो श्री मसानी की ज्यादातर दलीलो का खण्डन हो जाता है ।

उन्होंने जोर-गोर से यह भी कहा कि इस तरह की खेती के दुनिया में कहीं भी अच्छे नतीजे नहीं निकले । इस सम्बन्ध में भी मेरा कहना है कि इस तरह के आम वयान देना ज्यादा ठीक नहीं होगा । मैं उन्हें ऐसी मिसालें दे सकता हूँ, जहाँ सहकारी खेती कामयाब हुई है । श्री मसानी ने कुछ उदाहरण दिये । उन्होंने हमें बताया कि यूगोस्लाविया और पोलैण्ड में क्या हुआ ? ये सामूहिक खेती की नाकामयाबी के उदाहरण हैं । उन्होंने दो एक-दूसरे से खिलाफ बातों को एक में मिला दिया । उन्होंने उदाहरण दिया एक चीज का और उसे लागू कर दिया दूसरी चीज पर । दलील देने का यह अजीब तरीका है ! पहले तो वह कहते हैं कि जिस संयुक्त खेती का हमने प्रस्ताव किया है, वह सामूहिक खेती है और फिर वह कहते हैं कि सामूहिक खेती दूसरी जगहों पर नाकामयाब रही है और इसलिए संयुक्त खेती यहाँ नाकामयाब होगी । इससे उनके दिमाग की उलझन जाहिर होती है ।

मैं यूगोस्लाविया, पोलैण्ड, रूस या चीन की परीक्षा नहीं कर रहा हूँ । मैं दूसरे देशों में होनेवाली बहुत-सी बातों को पसन्द नहीं करता, कुछ दूसरी बातों को पसन्द करता हूँ । कभी हम समस्याओं की सगति में अपनी राय देते हैं, पर मुझे हमेशा इसमें सकोच होता है, क्योंकि जबतक कोई बड़े उसूल का सवाल दरपेश न हो, ईमानदारी की बात है कि मैं अपनेको दूसरे देशों का काजी बनने के लायक नहीं मानता । मुझे सब तथ्यों, परिस्थितियों और संयोगों की

जानकारी नहीं है और समाचारपत्रों या रिपोर्टों में प्रकाशित कुछ सामान्य तथ्यों के आधार पर फैसला देना ठीक नहीं होगा। मैं नहीं चाहूंगा कि दूसरे देशों के लोग कुछ सामान्य तथ्यों या रिपोर्टों के आधार पर मेरे देश के बारे में राय बनाने के चक्कर में पड़े। इसलिए मैं नहीं कह सकता कि यूगोस्लाविया, पोलैण्ड, रूस या चीन सही कर रहे हैं या गलत। वे ही ज्यादा ठीक जान सकते हैं।

## भारत की स्थिति

लेकिन भारत में हमें खास हालात का सामना करना है। हमारे यहां जमीन की औसत इकाइया बहुत छोटी है। हमारे यहां उनका औसत एक या दो एकड़ हो सकता है। मुझे पक्का मालूम नहीं है। निश्चय ही बहुत लोगों के पास एक एकड़ जमीन भी नहीं है। ऐसी हालात में आप क्या करेंगे? अगर हमारे यहां जमीन की इकाइयों का औसत बीस या पचास एकड़ हो तो बिल्कुल दूसरी बात होगी। उस दशा में हम दूसरी तरह सोचेंगे। मैं केवल नाम के लिए संयुक्त खेती या और किसी बात पर मुग्ध नहीं हूँ। किन्तु अगर किसी आदमी के पास एक एकड़ या इसके आस-पास जमीन हो, और भारत में ज्यादातर लोगों के पास इतनी ही जमीन है, तो उस जमीन से वह क्या कर सकेगा? जरूरी तौर पर, जैसा श्री मसानी ने कहा है कि अगर हम उसे अच्छे बीज, पानी, खाद और अच्छे औजार मुहय्या करें तो वह उसे सुधार सकता है। निश्चय ही, हम उसे ये सब चीजें धीमे-धीमे दे सकते हैं और हमें हर हालात में देनी भी चाहिए। किन्तु

ये सब देने के बाद भी क्या होगा ? हमारे पास जमीन के बड़े टुकड़े हो, तो भूमि में कुछ सुधार करके हम फायदा उठा सकते हैं । पर एक एकड़ जमीन का मालिक हमेशा अधपेट ही रहेगा । अगर मौसम कुछ अच्छा हुआ तो उसे कुछ ज्यादा खाने को मिल जायगा । पर फिर उसकी वही हालत हो जायगी । बेशक हमारे यहाँ इस समय खेती में बहुत ज्यादा लोग लगे हैं और उन्हें दूसरे धन्धों में लगाना होगा, उद्योगों में लगाना होगा । उद्योग बड़े, मध्यम अथवा कुटीर हो सकते हैं । जमीन पर आबादी का दबाव घटाना होगा । यह सही है । पैदावार बढ़ाने के लिए हर सम्भव उपाय किया जाना चाहिए, किन्तु मैं कहूँगा कि सैद्धान्तिक दृष्टि से या और तरह से भारत की वर्तमान परिस्थितियों में संयुक्त खेती हमारा सही लक्ष्य होगा ।

मैं फिर निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि हम लोगों की रजामन्दी से, और किसी तरह नहीं, आगे बढ़ना चाहते हैं और सैद्धान्तिक दृष्टि के अलावा, व्यावहारिक दृष्टि से भी आप इसी नतीजे पर पहुँचेंगे । मैं जानता हूँ कि किसान पुरातनवादी होते हैं और अगर मैं चाहूँ तो भी वे अपनी अगदतो को आसानी से नहीं बदलेंगे । मुझे उनके सामने कामयाबी की मिसालें रखनी होंगी, भाषण नहीं देना होगा । अगर मैं उनसे कहूँगा कि आपके पड़ोसी इसमें कामयाब हुए हैं तो और किसी बात की निस्वत इससे उन्हें ज्यादा यकीन होगा । इस तरह, आखिरकार यह सवाल भारत के किसानों के हाथों में है, न मेरे हाथों में है और न श्री मसानो के हाथों में । मैं उन्हें

किसी कार्यक्रम की अच्छाई के बारे में यकीन दिलाने की पूरी कोशिश ही कर सकता हूँ।

## किसानों को पूरा समय दीजिये

इस बीच, जब हम यह कहते हैं कि अगले तीन बरसों में हमें सेवा सहकारी संस्थाओं के निर्माण पर शक्ति केन्द्रित करनी चाहिए तो इसीसे जाहिर है कि हम इस बारे में जल्द-बाजी नहीं कर रहे हैं। किसानों को पूरा समय दीजिये। उनके लिए सेवा सहकारी समितियाँ संगठित कीजिये। ससद कोई कानून बनाने नहीं जा रही है। अगर वे खुद परिवर्तन करना चाहेंगे तो उन्हें कौन रोक सकेगा? सचमुच, मैं आपसे पूछता हूँ, आज भी किसी सहकारी समिति को संयुक्त खेती करने से कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता। दवाव डालने का तो कोई सवाल ही नहीं है। कोई नया कानून बनाने का भी सवाल नहीं है। समाज खुद ही काम को करने का फैसला करता है।

## सहकारी समितियों की मौजूदा हालत

सहकारी समितियों की मौजूदा हालत के बारे में मैं कुछ तथ्य देना चाहूँगा। छोटी ग्राम सहकारी समितियों के बारे में कुछ तथ्य ये हैं। मन् १९५०-५१ के अन्वीर में इन समितियों की संख्या १,१६,००० थी और मन् १९५६-५७ के अन्वीर में १,५६,०००। मन् १९५८-५९ के अन्वीर में यह संख्या १,७६,००० थी। ये ग्राम सहकारी समितियाँ हैं, बड़ी सहकारी समितियाँ नहीं। ग्राम सहकारी समितियों की मदद-

सख्या सन् १९५०-५१ मे ५१॥ लाख, सन् १९५६-५७ मे ९१ लाख, सन् १९५७-५८ मे ११० लाख थी। सन् १९५८-५९ का अनुमान १३८ लाख का है।

बड़ी सहकारी समितियों को ले तो सन् १९५६-५७ के अखीर मे उनकी सख्या १,९१५, सन् १९५७-५८ मे ४, ५२९ और सन् १९५८-५९ मे ६,३१८ थी।

माननीय सदस्य यह जानना चाहेंगे कि इन सहकारी समितियों ने ग्राम ऋण की कितनी रकम दी है। मैं यह कह दू कि उसका ८० फीसदी ग्राम सहकारी समितियों ने दिया है। बड़ी समितियों ने केवल २० फीसदी दिया है। सन् १९५०-५१ मे यह रकम २२ ९ करोड, सन् १९५५-५६ मे ४९ ६२ करोड, सन् १९५६-५७ मे ६३.३ करोड, सन् १९५७-५८ मे ९६ करोड और सन् १९५८-५९ मे १८० करोड रुपये थी। इस सबसे सहकारी समितियों की, खासकर छोटी सहकारी समितियों की, ठोस प्रगति का पता चलता है।

सयुक्त सहकारी खेती की बात करे तो सन् १९५७-५८ के अखीर मे भारत मे २००० सहकारी खेती समितिया थी, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि यहा 'सहकारी खेती' का शब्द कुछ लचीले तौर पर काम मे लिया गया है। कभी-कभी जमीन सहकारी समिति की होती है, मिलकियत भी समिति की होती है और उस जमीन मे खेती निजी रूप से की जाती है। अगर इस श्रेणी की सहकारी खेती समितियों को अलग कर दे, तो सयुक्त और सामूहिक खेती करनेवाली सस्थाओ की सख्या १,३५७ है। उनमे सयुक्त खेती की सस्थाए ९६६ और सामूहिक खेती की सस्थाए ३९१ है।

मैं नहीं कहता कि ये १३०० और कुछ संस्थाएं बहुत अच्छी या बहुत कामयाब या आदर्श सयुक्त खेती करनेवाली संस्थाएं हैं। लेकिन हर राज्य में कामयाब सयुक्त सहकारी खेती संस्थाएं मिलेंगी। उनकी संख्या पिछले दो-तीन सालों में बढ़ी है। किसीके दबाव से ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि किसानों ने बहुत-सी वजहों से खुद ही उन्हें अपनाया है। योजना-आयोग के कार्यक्रम-मूल्यांकन-संगठन की एक रिपोर्ट ढाई साल पहले प्रकाशित हुई है, जिसका शीर्षक है 'सहकारी खेती का अध्ययन'। इस रिपोर्ट में इन संस्थाओं का अलग-अलग मूल्यांकन किया गया है। योजना-आयोग अब और नये अध्ययन करा रहा है।

एक और सवाल है, जिसके बारे में कुछ लोगो ने कुछ शक जाहिर किया है। जमीन की मालिकी की ज्यादा-से-ज्यादा सीमा तय करने की कुछ आलोचना की गई है। इस सवाल पर इस सदन में नहीं, बल्कि उसके बाहर और कांग्रेस संगठन में तो कई साल और योजना-आयोग में भी चर्चा हुई है। माननीय सदस्यों को पता है कि योजना-आयोग ने उसकी बार-बार सिफारिश की है। दरअसल, कुछ राज्यों ने इस बारे में कदम भी उठाये हैं।

मैं इस मुद्दे पर जोर देना चाहता हूँ कि सहकारी खेती या जमीन की मालिकी की अधिकतम सीमा के बारे में ये फैसले अचानक नहीं किये गए हैं। इन सवालों पर सालों बहस-मुवाहता हुआ है। दरअसल, हमारी इस बात के लिए आलोचना हुई है और वह गायब नहीं भी है कि हम इस दिशा में बहुत धीमे चले हैं। जो हो, उनपर सोच-विचार किया गया, खास समितियाँ नियुक्त की गईं, जिनके सदस्यों में कांग्रेसियों



को और प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों को शामिल किया गया । इन समितियों ने सिफारिशों की और उनपर फिर चर्चा हुई । इस तरह जो फैसले किये गए हैं, उनके पहले काफी चर्चाएँ हुई हैं और सवाल के हर पहलू पर सोच-विचार किया गया है ।<sup>१</sup>

---

१. लोक सभा में दिये गए भाषण से—१६ फरवरी, १९५६

## दलगत राजनीति से अलग

कांग्रेस द्वारा निर्धारित कृषि-नीति को अमल में लाने में कोई समूह, दल या व्यक्ति सहयोग दे तो उसका स्वागत है। हम नीतिषो पर चलते हैं, इन्सानों या समूहों के आधार पर नहीं। इसलिए इसी नीति पर अमल खासतौर से गावों में या और भी निचली सतह पर करना होगा, और वहां हम दलगत राजनीति का प्रवेश नहीं चाहते। उससे गरीब ग्रामीण उलझन में पड़ जायगा।

हमारा मौजूदा कार्यक्रम मोटे तौर पर यह है कि जमीन की मालिकी को अधिकतम सीमा तक तय की जाय, ग्राम सहकारी समितियाँ और सेवा सहकारी समितियाँ कायम की जाय, आगे जाकर हम गाव की सतह पर सहकारी खेती शुरू करना चाहते हैं। इसमें हम सभी तरह के सहयोग का स्वागत करेंगे।

गाव में कौन-से संगठन काम करते हैं ? वहाँ ग्राम पंचायत है, ग्राम सहकारी समिति है या होनी चाहिए। सामुदायिक बिकास खण्ड है। गाव की सतह पर ये खास संगठन हैं। हम नहीं चाहते कि इन संगठनों में कोई दल दलों की हैसियत से

भाग ले । वहां पूरे सहयोग के लिए दरवाजा खुला है । उसके ऊपर भी सामुदायिक विकास-खण्ड-सलाहकार-समितियां हैं, जो विकास-खण्ड के ऊपर भी है ।'

।

: ८ :

## सामूहिक खेती का हौआ

हमने हाल में सहकारी खेती का लक्ष्य स्वीकार किया है। लोग जब चाहेगे तभी उसपर अमल किया जायगा। जमीन की मालिकी की अधिकतम सीमा के बारे में और अनाज के थोक व्यापार के बारे में फैसले किये हैं। आप कहते हैं कि उसका काफी जवानी विरोध हुआ है। मैंने इस विरोध को दिलचस्पी से देखा है, क्योंकि उसका पाच फीसदी तर्कसंगत है और ९५ फीसदी के पीछे जज्जवाती जोग है। उस विरोध के शब्दों में आवेश और क्रोध है। जब मैं ये तर्क-कुतर्क पढ़ता हू तो सोचता हू कि उस निहित स्वार्थ से बड़ा आवेश दूसरा नहीं हो सकता, जो अपने भविष्य के विषय में चिन्तित हो।

कुछ लोगो ने इन उद्देश्यों की जिस तरह चर्चा की है, उससे कम-से-कम मुझे बहुत ही गैर-मामूली तजुर्बा हुआ है और दूसरों को भी हो सकता है। बेशक, हर सवाल के दो पहलू होते हैं। लेकिन इसके अलावा, यह सहकारिता है क्या चीज ? क्या यह भोषण क्रान्ति है, कोई क्रान्तिकारी शब्द है, जिसने लोगो के दिमागो को उतना परेशान कर डाला है ? मेरा यह खयाल था कि आज दुनिया में सहकारिता के उमूल

को सब लोग मजूर करते हैं। इसमें कोई शक नहीं हो सकता। भारत में भी, भले ही हम पिछड़े हुए हों, सहकारी क्षेत्र में हमने काफी प्रगति की है।

आप अपने भाषण में सुझाव देते हैं—“सहकारी खेती की कुछ नमूने की योजनाएं शुरू कर देखिये।” मुझे ताज्जुब है कि आप कहते क्या हैं और भारत में अबतक इस विषय में जो कुछ हो चुका है, उसे देखने की आपने तकलीफ गवारा की है या नहीं। उस दिन मैंने ससद में भी कुछ आकड़े दिये थे और अबतक बिना किसी बड़े प्रयास के इस दिशा में जो काम हुआ है, उसकी ओर आपका ध्यान खींचता हूँ। यह भले ही काफी न हो, लेकिन काफी उल्लेखनीय है। यह सही है कि पुराने जमाने में सहकारी समितियाँ खासतौर पर ऋण देनेवाली सहकारी समितियाँ होती थीं, पर अब हम सेवा बहुदेशीय सहकारी समितियों की बात करते हैं।

आपको यह जानकर अचरज होगा कि देश में सैकड़ों सहकारी खेती की संस्थाएँ कायम हो चुकी हैं और ये बिना किसी सरकारी कोशिश के कायम हुई हैं। लोगों ने, किसानों ने, उनका गठन किया है। फिर भी सहकारी समितियों की इस तरह चर्चा की जाती है, मानो वे कोई बहुत खतरनाक और हैरतअगेज संस्थाएँ हैं और उनको महज छू लेने से सामूहिक खेती की भयंकर व्यवस्था जन्म ले लेगी, और सामूहिक खेती को और भी ज्यादा भीषण चीज—साम्यवाद की निशानी—माना जा रहा है।

## वाद-विरोधी

हम इस तरह नहीं सोचते और मैं यह साफ कह देना चाहता हूँ कि हम साम्यवाद के खिलाफ नहीं हैं और पूँजीवाद के भी खिलाफ नहीं हैं। मैं इस नजरिये का विरोधी हूँ और मेरा जैसा दिमाग है, उसमें अगर मेरे सामने कोई यह नजरिया रखता है तो वह मुझे उस दिशा में जाने को बढावा देता है, जिस दिशा में वह मुझे जाने से रोकना चाहता है। किसी भी जिदा-आदमी की यही स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी। मैं अपने देश की राजनीति में वाद-विरोधी धन्धा समझ नहीं पाता, जो आज को दुनिया में इतना ज्यादा चल रहा है।

लोग कहते हैं कि एशिया में, भारत और चीन में तेज होड़ है। मेरे मन में तो चीन के साथ होड़ करने की कोई भावना नहीं है। मैं नहीं जानता, किन्तु मुमकिन है, हमारे मकसद बिलकुल समान न हों। कुछ हद तक वे समान हैं—यानी हम जिन्दगी के स्तर को ऊँचा उठाना चाहते हैं। कुछ हद तक उनमें भेद है। जो हो, मेरे मन में होड़ की भावना नहीं है। दूसरों को अपने देश में जो कुछ करना हो, शौक से करे। उसका विचार करना मेरा काम नहीं है। मैं उनसे सीख सकता हूँ, सीखूँगा। अपने देश के लोग क्या चाहते हैं, वही मैं करूँगा और अगर कोई हमसे कुछ सीखना चाहे तो उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं।

यह नजरिया ही गलत है कि हम इस देश के खिलाफ हैं और उस देश के साथ हमारी होड़ है। मैं इसे अन्तर्राष्ट्रीय निगाह से और राष्ट्रीय निगाह से गलत समझता हूँ। किसी

ने मुझसे कहा कि सहकारी खेती सामूहिक खेती का रूप ले लेगी और उससे साम्यवाद आ जायगा । मैं कहता हूँ कि मैं इससे नहीं डरता । मैं नहीं समझता कि क्यों लोगो को डराने के लिए आदमी इस तरह शब्दों को उछालते रहते हैं ।

मैं सामूहिक खेती को पसन्द नहीं करता । जहातक मैं देख सकता हूँ, मैं नहीं समझता कि वह हमारे देश के लिए मौजू है या हो सकती है । हम उसपर अमल नहीं करेंगे । लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कुछ सामूहिक फार्म हैं । हमारा देश बहुत बड़ा है और उसमें भाति-भाति की विविधताएँ हैं और हम सबको सहन करते हैं । किसी भी सरकारी तन्त्र ने दबाव नहीं डाला है । कुछ किसानों ने उसका इस्तमाल करने की इच्छा जाहिर की है ।

जो हो, सहकारी फार्म हमारे मकसद हैं और देश की आज की हालत को देखते मौजू है । हमारे यहाँ की जमीन की इकाइया बहुत छोटी हैं । मैं दूसरे देशों को सलाह नहीं देता कि उन्हें क्या करना चाहिए । उनको अपने हालात, अपनी आर्थिक प्रगति और अपने जटिल वातावरण को ध्यान में रखकर काम करना होगा । हमको—मुझे और आपको—अपने देश के हालात के मुताबिक चलना होगा ।

## जमीन की छोटी इकाइयाँ

भारत में जमीन की इकाइया बहुत छोटी हैं । औसत इकाई एक एकड़ या उससे कुछ ज्यादा होगी । ऐसी हालत में आप क्या करेंगे ? हमारे किसान किस तरह तरक्की कर सकेंगे ? उन्हें अच्छे बीज, अच्छे खाद आदि देकर आप उनकी

चाहे जितनी मदद करे, उसका बड़ा नतीजा नहीं निकलेगा। बेशक, वे कुछ तरक्की करेंगे, किन्तु गरीबी की चक्की से कभी बाहर नहीं आ पायेंगे। मैं ऐसे भविष्य की कल्पना करने के लिए तैयार नहीं हूँ, जिसमें हमारे देश के बहुसंख्यक किसान जैसी-तैसी जिन्दगी बसर करे। इसके बजाय मैं अपने यहां लाखों क्रान्तियों का स्वागत करूंगा।

हम यह बुनियादी बात याद रखें और किसी भी प्रकार के हौओं से डरे नहीं। सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा डराने-वाली चीज भारत की गरीबी है, जिससे कि करोड़ों इन्सान पीड़ित हैं। चाहे जिस क्षेत्र में हम जो भी कोशिश करें, हमें इस चीज को याद रखना होगा। हम महसूस करते हैं कि हम गरीबी का जल्दी-से, अचानक खात्मा नहीं कर सकते। उनका खात्मा करने में हमारी पीढ़ियां गुजर जायेंगी, लेकिन हमें उस दिशा में आगे बढ़ना होगा।

बेशक, जमीन पर बहुत ज्यादा आदमी निर्भर करते हैं। जमीन पर दबाव कम करना होगा और हमें लोगों को उद्योगों में—बड़े, बीच के, छोटे और कुटीर उद्योगों में लगाना होगा। मेरे खयाल में यह किया जा सकता है और किया जायगा और हमारी रफ्तार बहुत धीमी होने की जरूरत नहीं।

## दबाव नहीं

असल बात यह है कि जमीन पर सहकारी ढंग से खेती करनी होगी। हम नहीं कहते कि हम सहकारी खेती से शुरू-आत करें। ऐसा कुछ नहीं है। हमने कहा है कि हमें देशभर में सेवा सहकारी समितियां कायम कर देनी चाहिए। हमारा



सुझाव है कि तीन साल में यह काम खत्म कर लिया जाय । हमारे देश में बड़े-छोटे कोई साढ़े पाँच लाख गाव हैं । अन्दाज है कि हमें दो लाख सेवा सहकारी समितियाँ बनानी होंगी । वजह यह है कि कुछ गाव बहुत छोटे हैं । यह सख्या कोई बहुत डरानेवाली नहीं है । जब ये सेवा सहकारी समितियाँ काम करने लगेंगी, तब लोग सहकारी खेती अपनाने के लिए आजाद होंगे । हम इसके लिए कानून नहीं बनाना चाहते, कोई दबाव नहीं डालना चाहते । लोग खुद फैसला करे या हो सकता है कि हम जाकर उन्हें खुद फैसला करने को बढावा दें, यह अलग बात है । यह हमारा अधिकार है और हम जरूर ऐसा करेंगे ।

फिर यह जोर-गुल क्यों ? मानो कोई बहुत ही गलत काम हो गया है, जिससे लोगों का भारी नुकसान हो जायगा । मेरी समझ में यह बात नहीं आती । क्या हमारी विवेक और तर्क-शक्ति गायब हो गई है और हम डरते हैं कि कोई हमारा पाँव कुचल देगा या हमारे निहित स्वार्थ को धक्का पहुँचा देगा और यह निहित स्वार्थ हमारे शरीर के अंग से भी कोमल है । कोई भी निहित स्वार्थ, जो अपने देशवासियों के रास्ते में आता है, दुनिया में और भी कम टिका रह सकता है । हम किसीके हिस्से पर चोट नहीं करना चाहते, पर यह याद रखने की बात है कि आज भारत में सम्पत्ति की विषमता काफी अधिक है । जब हम लोगों की खर्च करने की ताकत का अन्तर देखते हैं तो भोग-विलास और तड़क-भड़क पर होनेवाला खर्च खटकता है । कोई भी देश और खासकर राजनैतिक दृष्टि से लोकतन्त्री देश, यह सब कैसे वर्दाश्त कर

सकता है ? इसीलिए जमीन की मालिकी की ज्यादा-से-ज्यादा सीमा तय करने या अनाज का राजकीय व्यापार शुरू करने आदि की जरूरत है ।

जमीन की मालिकी की हदबन्दी एक मामूली सुधार है । मैं सहकारी खेती के सवाल पर बहस कर सकता हूँ । यह वाकया है कि जुदा-जुदा देशों में सामूहिक खेती हो रही है । मेरे खयाल में वह कनाडा में काफी पैमाने पर हो रही है, लेकिन कनाडा समूहवाद की ओर नहीं जा रहा है । लोग ये बातें नहीं जानते ।

सहकारी समितियों के बारे में एक अहम मुद्दा यह है कि अगर सहकारी आन्दोलन को भारत में सफल होना है तो उसके पहले सावधानी के साथ शिक्षण और प्रशिक्षण देना होगा । महज यह कहने से काम नहीं चलेगा कि 'सहकारी समिति बना दो और गांव के लोगो को उसे चलाने दो ।' मैं मजूर करता हूँ कि हमने प्रशिक्षण पर काफी ध्यान नहीं दिया है । हमें लोगों को सावधानी से प्रशिक्षण देना होगा । यह काम हमें पूरा करना है और जिस हद तक हम लोगों को प्रशिक्षित कर सकेंगे, उसी हद तक सहकारी आन्दोलन सफल होगा ।<sup>१</sup>

---

१ वाणिज्य व्यापार मण्डल के वार्षिक अधिवेशन के उद्घाटन-भाषण से, ७ मार्च १९५६

## ग्राम-समाज का नया रूप

मैं इस बात पर सन्तोष प्रकट करना चाहूंगा कि सहकारिता और सहकारी खेती का सदन के कुछ सदस्यों ने और उसके बाहर कुछ लोगो ने तेज और आक्रामक विरोध किया है। दरअसल, यह अफसोस की ही बात होती, अगर इस तरह के कदम को चुपचाप और बिना सोचे-विचारे मान लिया जाता।

मैं इसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस विषय को समझा जाय, उसे जानदार विषय माना जाय और दूसरी बातों की तरह मानकर भुला न दिया जाय।

मुझे मानना होगा कि मैं भली प्रकार समझ नहीं पाया हूँ कि सहकारी खेती का विरोध क्यों और किस बुनियाद पर किया जाता है। बेशक, मैं तर्क-रहित आवेग, पूर्वाग्रह, अज्ञात चीज को न समझ पाने की कठिनाई और हर नई चीज के डर को समझ सकता हूँ। कोई भी कदम आगे उठाते समय इनका हमेशा सामना करना ही पड़ता है। लेकिन पूरी कोशिश करने के बावजूद सहकारिता और सहकारी खेती के खिलाफ दी जानेवाली दलीलो और कारणों को मैं समझ नहीं पाया हूँ।

हम क्या चाहते हैं ? मोटे तौर पर कहे तो हम अपने देशवासियों के रहन-सहन की सतह ऊँची उठाना चाहते हैं,

पैदावार बढ़ाना चाहते हैं, ताकि जमीन उससे सम्बन्ध रखने-वाले लोगो और देश को पहले से ज्यादा फायदा पहुंचा सके। हम ज्यादा अच्छा सामाजिक संगठन बनाना चाहते हैं—ऐसा संगठन, जो हमारे उद्देश्यों को पूरा कर सके। इस सवाल को हल करने के दो रास्ते हैं : भावात्मक और नकारात्मक। हम नकारात्मक उपाय का विचार करें, क्योंकि माननीय सदस्य इस विचार का जो विरोध करते हैं, उनका दृष्टिकोण नकारात्मक है।

नकारात्मक दृष्टिकोण यह है—यह काम मत कीजिये। वह खतरनाक है। लोग उसे पसन्द नहीं करेंगे और गड़बड़ होगी। कभी यह भी कहा जाता है कि उससे पैदावार घट जायगी। अगर किसी कदम के फलस्वरूप पैदावार घटती है तो वह गलत कदम होगा। इसमें दलील की गुजाइश नहीं, क्योंकि हम पैदावार बढ़ाना चाहते हैं।

अगर हम कोई कदम नहीं उठाते तो हमारी कृषि-अर्थ-व्यवस्था का क्या हाल होगा? हमारे यहां ऐसे किसान हैं, जिन्हें सिर्फ जिन्दा रहने के लिए बड़ी कशमकश करनी पड़ती है, कुछकी हालत कुछ अच्छी होगी तो कुछ की बदतर। खराब मौसम आया और किसानों की कमर टूट जाती है।

यह सोचने की बात है कि इसका नतीजा क्या होता है। हालात ज्यो-के-त्यो बनाये रखने का यह अर्थ होगा कि आप किसानों और देश की गरीबी को हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। मुझे यकीन है कि इस नतीजे को कोई भी जान-बूझकर मजूर नहीं करेगा। हा, बिना सोचे-समझे किया जा सकता है, जैसाकि कुछ माननीय सदस्यों ने कर लिया मालूम देता है,

लेकिन विचारशील लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब तरक्की करना चाहते हैं। इसलिए हम हालात ज्यों-के-त्यों बने नहीं रहने दे सकते। हम यह मजूर नहीं कर सकते कि भारत गरीब बना रहे या हमारे किसानों की गरीबी जारी रहे।

मुझे जरा भी शक नहीं है कि सहकारी समितियों का रास्ता सही है और सहकारी खेती हमारा सही मकसद हो सकती है। बेगक, कुछ आलोचना मुनासिब हो सकती है और कुछ सवाल उठ सकते हैं। यह सवाल पूछा जा सकता है कि इस समय भारत के सब हिस्सों में हालात सहकारी खेती के कहातक अनुकूल हैं? कोई यह भी कह सकता है, और सही तौर से कह सकता है कि 'बिना काफी प्रशिक्षण दिये, बिना प्रशिक्षित आदमियों के, आप सहकारी खेती नहीं करा सकते। यह नहीं हो सकता कि उसके हक में कानून बना दिया जाय और उसके बाद सबकुछ अपने-आप होने लगे।' यह सही आलोचना है और हम लोगों को प्रशिक्षण देकर और आवश्यकता के अनुकूल वातावरण बनाकर उसका उत्तर दे सकते हैं। यह इस समस्या के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा। लेकिन महज यह कहने से काम न चलेगा कि सहकारी समितियाँ या सहकारी खेती मौजू नही है, क्योंकि वे नई चीजें हैं और भारतीय जनता की प्रतिभा के विरुद्ध हैं और इसलिए हम उन्हें नहीं अपनायेंगे। इसका कोई मतलब नहीं। यह अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। अगर आप उसे मान लेते हैं तो हमेशा गरीबी में डूबे रहना मजूर कर लेते हैं, क्योंकि नया कदम उठाये बिना आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते।

इसके विपरीत, यह कहना भी सही नहीं होगा कि सहकारी खेती अच्छी है और कल ही हमें सब जगह उसे अपना लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना मुश्किल होगा। मैं मानता हूँ कि यह व्यावहारिक नहीं होगा। हमको भूमिका तैयार करनी होगी, लोगों का दिमाग बनाना होगा, हमें उनको अपने अनुकूल बनाना होगा।

### स्वेच्छिक स्वीकृति

कुछ हल्कों में स्वेच्छिक स्वीकृति का सवाल उठाया गया है। यह भी एक अजीब सवाल है। जबतक हमारा संविधान अपने मौजूदा रूप में बना हुआ है, यह काम लोगों की स्वेच्छिक स्वीकृति से ही हो सकता है। अगर संविधान टूट जाय अथवा बदल जाय तो उसके बाद मैं नहीं जानता कि क्या होगा, लेकिन जबतक हमारा लोकतन्त्री संविधान बना है, ये आशंकाएं और डर बे-बुनियाद हैं। मैं एक कदम और आगे जाऊंगा। देश की वर्तमान दशा में, एक विशाल देश में, दबाव के तरीकों से इस प्रकार का परिवर्तन करना कठिन होगा, मैं कहता हूँ, करीब-करीब नामुमकिन होगा। आप ऐसा कर नहीं सकते। आप कानून बना सकते हैं, लेकिन आपको लोगों से उस कानून पर अमल कराना होगा, सैकड़ों और लाखों आदमियों से अमल कराना होगा, नहीं तो आप काम-याब नहीं होंगे, भले ही आप कुछ हद तक दबाव भी क्यों न डालें।

इसके खिलाफ, यह कहना मुझे बिल्कुल बेहूदा लगता है कि एक किसान सारे गांव को रोककर रख सकता है और

उसे आगे बढ़ने नहीं दे सकता । मैं इस हालत को स्वीकार नहीं करता । मैं यह बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ । अगर आप यह हालत मजूर कर लेते हैं तो फिर इस ससद में या किसी ग्राम-पंचायत या ग्राम-सरकारी समिति में कोई भी कानून-कायदा नहीं बन सकेगा । यह नामुमकिन है । अगर ग्राम-सहकारी समिति कोई काम करना चाहती है और एक आदमी कहता है—‘मैं नहीं करने दूँगा’, तो ग्राम-सहकारी समिति बेबस हो जायगी । इस तरह कोई सहकारी समिति नहीं चल सकती, कोई पंचायत काम नहीं कर सकती, कोई विधान-सभा नहीं चल सकती । लोकतंत्र का यह मतलब नहीं कि एक आदमी सारे समाज का रास्ता रोक दे । इस प्रकार बुनियादी बात यह है कि सहकारी खेती पर तभी अमल होगा जब आम तौर पर लोग उसे स्वीकार करने को राजी होंगे ।

मैं यह बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ कि अगर हम किसी नीति को सही समझते हैं तो हम उस नीति को स्वीकार कराने के लिए पूरा प्रोत्साहन देंगे, किन्तु दबाव नहीं डालेंगे । हम बढावा अवश्य देंगे । हम अच्छा काम करनेवालों को बार-बार सम्मान देंगे । अच्छे कार्यकर्ता को ज्यादा मजदूरी देकर हम उसका सम्मान करते हैं । वह पैदावार बढायगा और हम उसे ज्यादा मजदूरी देंगे । इस प्रकार का बढावा आप हमेशा देते हैं । दरअसल, मैं इस प्रकार की पद्धति सभी कारखानों, कृषि-फार्मों, संयंत्रों और राजकीय सेवाओं में नहीं दाखिल करना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ सबकुछ समय के पैमाने से नापा जाता है ।

## भारत के हालात

मैं सदन से कहना चाहता हूँ कि इन सवालों पर सोच-विचार करते समय शायद हम थोड़े भटक जाते हैं। मैं यह पूरे आदर के साथ कहता हूँ। हम सवाल पूछते हैं—यूगोस्लाविया ने क्या किया है? किसी और देश ने क्या किया है? हम पूछते हैं—क्या यह लोकतंत्र होगा? बेशक, हमको यूगोस्लाविया, रूस, चीन या अमरीका, इंग्लैण्ड या जर्मनी के उदाहरण से फायदा उठाना चाहिए, लेकिन हम इन सवालों को ऐसी कसौटी पर परखने की कोशिश करते हैं, जो जब-तब फायदेमंद हो सकती है, पर आज वह ज्यादा मौजूद नहीं है। हमको भारत की परिस्थितियों पर विचार करना होगा। हमें सोचना होगा कि हम अपने मकसद को कैसे हासिल कर सकते हैं। जब मैं भारत के हालात की बात करता हूँ तो मेरा मतलब सिर्फ कृषि-सम्बन्धी हालात से ही नहीं, बल्कि लोगों की दशा से भी है। मुझे उसूलन जरा भी सदेह नहीं है कि सहकारिता, सहकारी प्रयास, शायद ऊँचे कलात्मक प्रयास को छोड़कर, हर मानव-प्रवृत्ति के क्षेत्र में अच्छा है। ऐसे कलात्मक प्रयास को छोड़कर हर दूसरी प्रवृत्ति में सहकारिता का मार्ग उत्तम है। जहातक उसूल का सवाल है, इस विषय में कोई शक नहीं हो सकता। आप यह आपत्ति पेश कर सकते हैं कि व्यवहार में लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हमें इसका उत्तर देना है, लेकिन यह जीवन का ज्यादा अच्छा तरीका है और दरअसल जब आप ज्यादा आबादीवाले समाज में रहते हो तो यह लाजमी तरीका हो जाता है। जहाँ आबादी छितरी हुई हो, वहाँ बड़े कृषि फार्म ठीक हो सकते हैं और हर फार्म



का अपना अलग अस्तित्व हो सकता है। वैदिक युग में जमीन की मालिकी की प्रणाली उस समय के लिए मौजूद रही होगी, जबकि जमीन के बड़े-बड़े हिस्से और वन-प्रदेश उपलब्ध थे और आबादी निस्वतन्त्र कम थी, लेकिन देश की आज की आबादी को देखते हुए वैदिक युग की प्रणाली को नहीं चलाया जा सकता। आज आबादी सैकड़ों गुनी बढ़ गई है और बढ़ रही है।

इस समस्या के दो हल हैं : एक सहकारिता और अखीर में सहकारी खेती है और दूसरा लोगों को खेती से हटाकर उद्योगों में लगाना है। हमारे देश में शहरी और कृषि-जन-संख्या का क्या अनुपात है और उसमें क्या हेर-फेर हुआ है, यह बात हमारे देश के इतिहास में गैर-मामूली-सी है और सदन के बहुत-से माननीय सदस्यों को इसका बिलाशक पता होगा। यूरोप के अधिकांश औद्योगिक देशों में, सारी १९वीं सदी में, शहरी आबादी बढ़ी है। शहरी आबादी से मेरा मतलब खासकर उद्योगों में काम करनेवाली आबादी से है। शहरी आबादी के मुकाबले कृषि-आबादी का अनुपात ५०:५०, ६०:४०, ४०:६० और इसी तरह का था। बेशक, अमरीका में कृषि-आबादी बहुत कम है। भारत उन थोड़े से देशों में है, जहाँ पूरी १९वीं सदी में और कुछ हद तक बीसवीं सदी में भी शहरी आबादी की जगह देहाती आबादी बढ़ी है।

इसका अर्थ क्या है ? इसका अर्थ यह है कि काम के मौकों का और औद्योगिक प्रवृत्तियों का अभाव रहा और हर कोई रोजी के लिए जमीन का सहारा लेता था और जमीन पर बोझ बढ़ाता था। जमीन खाली नहीं थी। नये लोगों के

प्रवेश करने के पहले ही भूमि पर काफी लोग मुनहसिर थे । भारत की गरीबी का यह बुनियादी कारण है, यानी भूमि पर मनुष्यों का बढा हुआ भार । इसलिए हमें भूमि पर से लोगो को हटाना होगा और उन्हें कुछ दूसरे धंधो मे लगाना होगा । 'हटाने से' मेरा यह मतलब नहीं कि उन्हें कलकत्ता या बम्बई मे ले आया जाय और वहाँ बसा दिया जाय, बल्कि वही उनके लिए औद्योगिक प्रवृत्तियां मुहय्या की जायं ।

दूसरा हल भूमि के क्षेत्र मे सहकारी प्रयास अपनाना है । यह तर्क-संगत, वैज्ञानिक और युक्ति-युक्त तरीका है । इसके अलावा, इससे हमारे दूसरे लक्ष्य यानी भूमि की पैदावार बढाने के लक्ष्य को पूरा करने मे मदद मिलेगी । जाहिर है कि दूसरी बातें समान हो और ज्यादा अच्छी तकनीक और तरीके काम मे लाये जाय तो पैदावार मे बढोतरी होगी । पुराने औजारो अथवा खराब तरीको से पैदावार बढाने की कल्पना करना अपने-आपमे असंगत है ।

जमीन की छोटी इकाइयो मे ज्यादा अच्छे तरीके काम मे नहीं लाये जा सकते । लेकिन एक बडा किसान, जिसके पास कई सौ एकड का फार्म हो, वह ज्यादा अच्छे तरीके अपना सकता है । मैं ट्रैक्टरो की बात नहीं कर रहा हूं । यह बात नहीं कि मैं ट्रैक्टरों का विरोधी हूं, किन्तु मेरे खयाल में देश के मौजूदा हालात मे ट्रैक्टर बडे पैमाने पर काम में नहीं लाये जा सकते । मैं तो ज्यादा अच्छे औजारो और ज्यादा अच्छे तरीकों की बात सोच रहा हू । उनका जमीन की छोटी इकाइयो मे प्रयोग नहीं किया जा सकता । पहले तो छोटे, गरीब किसान के पास साधन ही नहीं होते । दूसरे, उसे सुधरे

औजारो और तरीको का शिक्षण नहीं होता । इन तरीको का प्रयोग करने के लिए बड़े फार्मों की जरूरत है । राजस्थान में विशाल राजकीय फार्म में इस समय बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम हासिल किये जा रहे हैं । यह पाच हजार एकड़ का फार्म है और जिन लोगो ने उसे देखा है, उन्होंने मुझे बताया है कि वहां अचरज में डालनेवाली फसले हुई हैं । मामूली तौर पर चार फुट की फसल वहां दस फुट ऊंची है ।

फिर भी दूसरे कारणों से मैं बहुत बड़े फार्मों के हक में नहीं हूँ । हमारा लक्ष्य ऐसी कृषि-अर्थ-व्यवस्था है, जिसमें छोटे फार्म होंगे और उन्हें देहाती सतह पर सहकारी ढंग से गठित किया जायगा । अगर इकाई बहुत बड़ी होगी तो सहकारिता बहुत कामयाबी से नहीं चलेगी । मैं नहीं चाहता कि सहकारी समिति का दायरा एक या दो गावों से बड़ा हो, क्योंकि बड़ी इकाइयों में निजी सम्पर्क नहीं रहेगा । उनमें अजनबी आदमी आते हैं, जिन्हें लोग जानते नहीं । उस दशा में दो बातें होगी । एक तो यह कि सरकारी अफसरों का प्रवेश होगा और मैं चाहता हूँ कि सरकारी अफसरों का, जहातक मुमकिन हो, दखल न हो । दूसरे, उस बड़े ग्राम-समूह में कुछ चालाक लोग कर्त्ता-धर्त्ता बन सकते हैं और दूसरों का भोपण कर सकते हैं । लेकिन छोटे गाव में, जहां लोग एक-दूसरे को जानते हैं, एक प्रकार की कुनवे की-सी भावना होती है । लोगो को पता होता है कि कौन खराब और कौन भला आदमी है । वे कम-ज्यादा मिल-जुलकर चल सकते हैं और लड़-झगड़कर भी एक साथ काम कर सकते हैं । यह विचार है, यानी एक या दो गाव मिलकर एक सहकारी समिति बनायेंगे और इस

प्रकार की दस या बारह समितियाँ आर्थिक उद्देश्यों के लिए अपना सहकारी सघ बना लेगी। छोटी इकाई परिणाम लाने में बेकार साबित हो सकती है या पूरी तरह से स्वावलम्बी नहीं हो सकती है, लेकिन सहकारी सघ ऐसा हो सकता है।

अगर लोग संयुक्त खेती करें तो बहुत अच्छा, लेकिन मैं उन्हें यह करने के लिए नहीं कहता, क्योंकि मैं यह महसूस करता हूँ कि संयुक्त खेती अच्छी होते हुए भी लोगों को उसे धीमे-धीमे अपनाना होगा। उसे थोपा नहीं जा सकता। आपको उसका मनोविज्ञान और व्यवहार सीखना होगा।

## प्रशिक्षण का महत्व

जहातक व्यवहार का सम्बन्ध है, मेरे खयाल से यह बड़े महत्व की बात है कि हम अभी से लोगों को, काफी लोगों को, उसकी शिक्षा दें। जबतक प्रशिक्षित सहकारी कार्यकर्त्ता नहीं होंगे, वह हर्गिज कामयाब नहीं होगी और प्रशिक्षण का मतलब यह है कि केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारें और सामुदायिक विकास आन्दोलन, सभी यह काम अलग-अलग सतहों और मात्रा में करते हैं। सबसे पहली बात यह कि कुछ ऊँचे दर्जे का प्रशिक्षण पाये हुए लोग होने चाहिए, जो अपने विषय के माहिर हों। हम अपने कृषि-कालेजों, देहाती संस्थाओं और दूसरी जगहों पर खास कक्षाएँ शुरू कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, हर कालेज में कुछ लोग सहकारिता के पूरे ज्ञाता और अनुभवी होने चाहिए। फिर कुछ ऐसे लोग होने चाहिए, जो उस स्टैण्डर्ड के न होते हुए भी काफी तजरबेकार हों। अखीर में, पंचों और सरपंचों को सहकारी समितियाँ और सामुदायिक

विकास आन्दोलन थोड़ा प्रशिक्षण दे । इस प्रकार प्रशिक्षण तीन भागों में बाँटा जा सकता है । एक, थोड़े शिक्षण का व्यापक आधार हो । दूसरा, काफी प्रशिक्षण का थोड़ा ऊँचा आधार हो और तीसरा, चोटी पर दरअसल बहुत ही उच्च शिक्षण पाये हुए लोग हो, यह जरूरी है ।

दूसरा पहलू मनोवैज्ञानिक है । अगर लोग सेवा सहकारी सस्था से शुरू करें और कामयाब हो तो उनके लिए अगला कदम सक्षिप्त होगा । फैसला मैं या ससद नहीं करेंगे । सेवा सहकारी सस्था फैसला करेगी । अगर वे हमसे मदद माँगे तो हम मदद देने की कोशिश करेंगे । अखीर में वे ही सेवा सहकारी सस्थाओं में अपने अनुभव की बुनियाद पर दूसरे क्षेत्रों में संयुक्त खेती के प्रयोगों को देखकर फैसला करेंगे । किसान सिद्धान्त की निस्वत मिसाल से प्रेरित होता है । मेरे खयाल से काम की यही मजिले है ।

मुझे यकीन है कि संयुक्त खेती अधिक पैदावार, अधिक एकता और वर्ग-भेदों को दूर करने के लिए जरूरी है । यह महत्व की चीज है । यह इसका मनोवैज्ञानिक अंश है । आप इस प्रकार धीमे-धीमे, अचानक नहीं, गाँव के सारे सामाजिक ढाँचे को बदल देंगे । सहकारी संगठन, पचायते और ये ग्राम-सस्थाएँ हमारे समाज के वास्तविक लोकतन्त्री आधार का निर्माण करेंगी । इसका मतलब है एक कदम के बाद दूसरा कदम उठाया जाय, कड़ी मेहनत की जाय और लाखों आदमियों तक पहुँचा जाय । इसका यह मतलब है कि तरीका बहुत ज्यादा कड़ा न हो । व्यापक दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट हो, लेकिन उसका प्रयोग बहुत अधिक कठोर न हो । भारत जैसे

विशाल देश में मैं किसी ऐसे कठोर प्रयोग के हक में नहीं हूँ, जिसे देश के हर हिस्से में लागू किया जाय। कभी-कभी गेहूँ उगानेवाले क्षेत्र के लिए जो प्रयोग उपयोगी होगा, वह धान उगानेवाले क्षेत्र के लिए उतना उपयोगी नहीं हो सकता है। हालात जुदा हैं और प्रयोग उन हालात के अनुसार ही होना चाहिए। प्रयोग लचकीला होना चाहिए और यह लाजमी है कि उसकी मजिले होगी। पहली मजिल मोटे तौर पर सेवा सहकारी समिति, बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति के गठन की होगी। अगली मजिल में संयुक्त खेती की सहकारी सस्थाओं का निर्माण होगा। यह सारे देश में एक ही रात में नहीं हो जायगा। धीमे-धीमे सेवा सहकारी समितियाँ संयुक्त सहकारी खेती समितियों में बदल जायगी। कुछ समय ऐसा निकलेगा जब दोनों साथ-साथ चलेगी और अनुभव हासिल करेगी।

## स्वामित्व की कल्पना

सदन को याद होगा, हमने कहा है कि भूमि की मालिकी जारो रहेगी। कुछ लोग कहते हैं, यह धोखा है और अगर हम सचमुच जमीन की मालिकी को कायम रखना चाहें तो भी हम उसपर कायम नहीं रह सकेंगे। मुझे नहीं मालूम कि मैं भविष्य के बारे में क्या कह सकता हूँ। मालिकी की यह कल्पना एक अजीब कल्पना है, जो युग-युगों में बदलती आई है। सदन को पता है कि आचार्य विनोबा भावे कहते हैं कि जमीन की मालिकी होनी ही नहीं चाहिए। मैं इस विचार का आदर करता हूँ और मुझे सचमुच बहुत खुशी होगी, अगर जमीन की मालिकी मिट जाय। लेकिन मैं नहीं सोचता कि आज ऐसा हो

सकता है। मैं इसका खण्डन नहीं करता, पर मैं आज उसे व्यावहारिक नहीं समझता और इसलिए उसपर जोर भी नहीं देता। लेकिन यह मालिकी की कल्पना सामुदायिक नहीं है। मान लीजिये, कोई बड़ी जायदाद है और सीमित दायित्ववाली हिस्सेदारों की कम्पनी है। एक आदमी १० फीसदी जमीन का मालिक है। लेकिन वह यह नहीं कह सकता—‘भूमि का यह खास टुकड़ा मेरा है।’ वह बड़े क्षेत्र के दस फीसदी का मालिक है। मालिकी हक काफी ठोस है। उसे लाभ का हिस्सा मिलना है। आज औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े देशों में ही जमीन का महत्व बहुत ज्यादा है। भूमि की सभी जगह कीमत है, लेकिन औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े देशों में उसकी ज्यादा कीमत है। पर जहाँ उद्योग पनपते हैं, स्टॉक और शेयर के रूप में मालिकी बनती है, मालिकी साख का रूप लेती है और निगाह से ओझल हो जाती है। साखवाला आदमी उद्योग शुरू करने के लिए चाहे जितनी पूजी जुटा सकता है। मालिकी की सारी कल्पना ही बदल रही है, फिर भी, हम एक गज जमीन पर बैठकर मालिकी पर जमे हैं और गर्व से कहते हैं, ‘यह एक गज जमीन मेरी है और उसे कोई नहीं छीन सकता।’ सामुदायिक जीवन के विकास के साथ इसमें भी तब्दीली होनी है। शहरों में पहले सड़कें और पुल निजी थे। अब दोनों ही सार्वजनिक सम्पत्ति बन गये हैं। रेलें भी सार्वजनिक सम्पत्ति बन चुकी हैं। निजी सम्पत्ति की कल्पना बदलती है और जनता और आदमी का उससे लाभ होता है। बदलता समाज मालिकी के इन बुनियादी रूपों के बारे में अपने विचारों में तब्दीली लाता है। यह होनेवाला है। उससे डरने की जरूरत

नहीं। दरअसल हमें उसका स्वागत करना चाहिए, बशर्ते कि उससे हमारे लक्ष्य की पूर्ति होती हो।

इस प्रकार आप इस समस्या पर जिस तरह से भी विचार करें, आपको इस नतीजे पर पहुँचना होगा कि हमारा भविष्य सहकारी प्रयोग पर निर्भर करता है। मैं कह दूँ कि सहकारी प्रयोग सिर्फ जमीन पर ही नहीं, बल्कि उद्योगों में भी मुनासिब है। फिलहाल हम सिर्फ जमीन का ही विचार कर रहे हैं।<sup>१</sup>

---

१ लोकसभा में दिया गया भाषण, २८ मार्च १९५६



## बुनियादी बातें

राष्ट्रीय विकास परिषद की पिछली बैठक में, मोटे तौर पर, सहकारिता-सम्बन्धी नीति मजूर की गई थी। उसके हर महत्वपूर्ण आधार के बारे में पूरी सहमति थी। बुनियादी बात यह है कि हर सहकारी समिति अपने सदस्यों में एक तरह का नजदीकी सम्बन्ध स्थापित करे। यही समन्वय का विचार है। उसका रूप सिर्फ एक तरह के बैंक जैसा न हो। वह केवल ऋण देनेवाली सहकारी समिति न हो। वह इतनी बड़ी भी न हो कि उसमें अजनबी लोग आजाय, वगैरा-वगैरा। यह भी स्वीकार किया गया कि मुख्य रूप से छोटी सहकारी समितियाँ हों। वे एकरस हों और उनमें अफसरों की दखलन्दाजी न हो। हा, अफसर लोग मदद जरूर करें। इन सब बुनियादी बातों को हरेक ने मजूर किया।

फिर कुछ दूसरे सवाल उठाये गए। पहले तो हमें आदिम-जाति क्षेत्रों को अलग करना होगा, यानी हम इन क्षेत्रों के लिए कोई समान और कठोर नियम नहीं बना सकते। हमें उनके साथ अलग तरह से बर्ताव करना होगा। उन क्षेत्रों में सहकारी समितियों को जुदा तरह से चलाना होगा। दूसरे शब्दों में, हमारी नीति लचीली होगी, किन्तु जो बुनियादी बातें मजूर की जा चुकी हैं, उनको कुदरतन लागू

एक सवाल जिसपर चर्चा हुई, यह था कि सहकारी समितिया बड़ी हों या छोटी। व्यवहार में ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि वास्तव में बड़ी सहकारी समितिया बनाई ही नहीं जाती, कुछ जगहों में ग्राम सहकारी समिति से थोड़ी बड़ी सहकारी बनाना मुनासिब हो सकता है। बेशक, जहाँ गांव बहुत छोटे हों, वहाँ दो-तीन गावों को एक सहकारी सगठन में शामिल किया जा सकता है और अखीर में इसका फैसला राज्य सरकार के हाथों में छोड़ देना होगा। अगर वह समझती है कि पाच-छ. गावों को एक सहकारी सगठन में शामिल कर लिया जाय तो ऐसा किया जा सकता है, लेकिन जहाँ तक मुमकिन हो, हमें यह नहीं करना चाहिए।

दूसरा सवाल यह था कि सरकार सहकारी सगठनों में शेयर (हिस्से) खरीदे या नहीं और इसपर काफी चर्चा हुई। हममें से कुछकी राय थी कि सरकार ऐसा न करे। हम स्वीकार करते हैं कि सहकारी सगठनों की मदद की जानी चाहिए। यह मदद रुपये के रूप में न होकर पैदावार बढ़ाने की योजनाओं में दी जाय। इन छोटे मुद्दों पर एक कमेटी विचार कर रही है, जो कल नियुक्त की गई थी, किन्तु, जैसा मैंने कहा, हम बहुत ज्यादा कड़े नियम नहीं बना सकते।<sup>१</sup>

१ राष्ट्रीय विकास परिषद की बारहवी बैठक का उद्घाटन-भाषण  
३ अप्रैल १९५६

## समस्याओं पर लचीला दृष्टिकोण

मैं अपने प्रारम्भिक वक्तव्य में मामूली सामुदायिक विकास आन्दोलन के बारे में विशेष न कहकर सहकारिता आन्दोलन की चर्चा करना चाहूंगा। सहकारिता आन्दोलन भारत के लिए या दुनिया के लिए कोई नया आन्दोलन नहीं है। हम सहकारी सगठनों का काफी तजरवा हासिल कर चुके हैं, लेकिन हमने जो व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है, उसमें कम-से-कम हमारे लिए कुछ नवीनता है। हमारा यह दृष्टिकोण कोई अचानक नहीं बना है। काफी गहरे सोच-विचार और चिन्तन के बाद हमने उसे अपनाया है।

### राष्ट्रीय विकास परिषद् का प्रस्ताव

कई महीनों पहले राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक हुई थी और उसने फैसला किया कि हमें इस कार्यक्रम पर अमल करना चाहिए और देश के हर गांव में सहकारी सगठन कायम करना चाहिए। इसपर गायद उन लोगों को ताज्जुब हुआ, जो इस विषय पर विचार नहीं कर रहे थे। कुछ समय बाद राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने नागपुर-अधिवेशन में न सिर्फ इसे मंजूर किया, बल्कि उसपर काफी जोर दिया। संयुक्त खेती के अन्तिम लक्ष्य पर विशेष जोर दिया। लेकिन कांग्रेस ने कहा

कि फिलहाल और अगले तीन साल हम सेवा सहकारी संगठन कायम करने पर ताकत लगावे ।

इसके बाद इस निश्चय पर कुछ उत्तेजना पैदा हुई, मानो कोई घातक कदम उठाया गया हो, यहातक कि इस सदन मे भी ऐसे भाषण दिये गए, जिनसे वक्ताओ की उत्तेजना और विरोध का पता चलता था ।

कुछ हफ्ते और गुजरे और इस सदन मे और शायद उसके बाहर भी हर किसीने मोटे तौर पर और बहुत मजबूती से इस दृष्टिकोण को मान लिया है । उन थोड़े-से हठी लोगो की बात अलग है, जो रोशनी तेज होने पर भी उसे नही देखेगे ।

ऐसे बड़े कार्यक्रम के सम्बन्ध मे व्यौरे पर मतभेद हो सकता है और वह स्वाभाविक है, किन्तु बुनियादी दृष्टिकोण मान लिया गया है और उसका स्वागत किया गया है । मेरे खयाल से देहाती जनताने उसका विशेष रूप से स्वागत किया है और उसीपर यह लागू भी होता है । मै नही कहता कि हर आदमी ने इसका स्वागत किया है या उसके हर व्यौरे का स्वागत किया गया है या उसे मान लिया गया है, पर उसको लेकर व्यापक दृष्टिकोण का स्वागत किया गया है ।

## नया सामाजिक ढांचा

शुरू मे मै इसका एक पहलू सदन के सामने रखना चाहूंगा । हम सहकारी आन्दोलन, ग्राम सहकारी समितियों या बड़ी सहकारी समितियो की बात करते है, किन्तु मै चाहूंगा कि इस विषय पर और भी व्यापक दृष्टिकोण से विचार किया जाय, इस दृष्टिकोण से विचार किया जाय कि हमे देहातों का

पुनर्गठन करना है और नई समाज-व्यवस्था की रचना करनी है। सहकारी सगठन या पचायत का बुनियादी स्वरूप सदस्यों का नजदीकी सम्पर्क, सामाजिक एकता और आपसी दायित्व है। धीमे-धीमे नये ग्राम-समाज की रचना के लिए यह जरूरी है। यह बहुत बड़ा काम है। जब हमने सामुदायिक विकास आन्दोलन शुरू किया तो हमारा यही मकसद था, भले हों हमने उसे संस्थागत रूप न दिया हो। संस्थागत रूप अब सहकारी सगठनों में प्रकट हो रहा है। अबतक सामुदायिक विकास-आन्दोलन ने देहात के लोगों को स्वावलम्बी बनाने, एक साथ काम करने, सहकार करने, अपने देहातो का निर्माण करने और हर मोर्चे पर, खासकर कृषि के मोर्चे पर, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। अब सहकारी संगठन सामने आ रहा है और उस मकसद को सगठनात्मक संस्थागत रूप दे रहा है।

## विशाल प्रयास

दूसरे गब्दों में यह विगाल प्रयास है कि जमीन की समस्या पर बुनियादी सामाजिक दृष्टिकोण लागू किया जाय। मैं 'विगाल' शब्द का इसलिए उपयोग कर रहा हूँ कि भारत का आकार विगाल है।

जमीन की छोटी-छोटी इकाइयों में व्यक्तिगत खेती के दूसरे विचार को हम नापसंद करते हैं। उससे तरक्की रुकती है। हम सामूहिक खेती के विचार को भी पसन्द नहीं करते। हम यह सहकारिता का दृष्टिकोण पेश करते हैं, जो हमारे बुनियादी आदर्शों के अनुरूप है।

वेगक, जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम सहकारिता के

विषय में बार-बार विचार करेंगे, उसमें फर्क करेंगे, बदलेंगे और बदलती परिस्थितियों के अनुरूप उसे ढालेंगे। इस प्रकार की समस्या को हल करने में लचीलापन जरूरी है। दो कारणों से कड़ा सिद्धान्तवादी या शास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाना मुनासिब नहीं होगा। एक तो यह कि भारत जैसे विविधतावाले देश में सिद्धान्तवादी और कठोर दृष्टिकोण अपनाना बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं होगा। दूसरे, यह स्वाभाविक है कि ऐसे विशाल आन्दोलन में, जिसका देश के ३६ करोड़ आदमियों से सम्बन्ध है, कड़ा दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता। इसलिए मैं सदन से इस फैसले पर व्यापक दृष्टि से विचार करने का अनुरोध करूंगा।

हम लचीले हों, लेकिन यह लचकीलापन इस हद तक न हो कि वह अस्पष्ट मामूली चीज बनकर रह जाय। यह बेकार होगा। इसलिए हमें अपने देहातो में सहकारी आन्दोलन के स्वरूप की काफी स्पष्ट कल्पना होनी चाहिए।

### ग्राम ऋण सर्वेक्षण

इस बारे में सदन को ग्राम ऋण सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों को याद करना है। सर्वेक्षण का नतीजा यह हुआ है कि बहुत-से अच्छे सुझाव और प्रस्ताव सामने आये। लेकिन ग्राम सहकारी समितियों के बारे में उसकी सिफारिश इस खेदजनक अनुमान पर आधारित थी कि हमारे ग्रामीण इतने पिछड़े हुए हैं कि उन्हें ज्यादा जिम्मेदारी नहीं सौंपी जा सकती। मैं निजी तौर पर इस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करता।

दूसरा दृष्टिकोण यह है कि सहकारी आन्दोलन का मूल

तत्त्व यह है कि वह गैर-सरकारी, स्वावलम्बी और आत्म-निर्भर होना चाहिए और उसमें सदस्यों के बीच गहरा सम्पर्क और पारस्परिक दायित्व की भावना होनी चाहिए ।

दो या तीन साल तक चर्चा चली । ग्राम ऋण सर्वेक्षण के कारण और बैंको से, खासकर रिजर्व बैंक से, रुपया मिलने के कारण बड़ी सहकारी समितियां बनाने की प्रवृत्ति ने जोर पकड़ा । मैं नहीं कहता कि बड़ी सहकारी समितियां कामयाब नहीं हुईं, लेकिन धीरे-धीरे यह राय पक्की हुई है कि छोटी ग्राम सहकारी समितियां बननी चाहिए और इसके विविध कारणों का मैं निर्देश कर चुका हूँ । सच्चा सहकारी सगठन वह है, जिससे आप लोगों को आगे बढ़ा सके, लोग एक-दूसरे से सम्पर्क कायम कर सकें और आपसी जिम्मेदारी और सामाजिक एकता का विकास हो । अगर आप चाहते हैं कि लोग विकास करें और आप वास्तविक सहकारी ढांचे की नींव रखना चाहते हैं तो वह सगठन बहुत बड़ा नहीं, बल्कि छोटा होना चाहिए ।

इस खाई को पाटने के लिए एक जुदा तरीका सुझाया गया । वह यह कि ग्राम सहकारी समितियां बनाई जाय, लेकिन दस, बारह या पन्द्रह ऐसी समितियों का हम एक सहकारी सघ भी बना लें, ताकि उनकी मामूली तौर पर देख-भाल की जा सके और बैंक उन्हें कुछ कामों के लिए सहायता दे सके ।

राष्ट्रीय विकास परिषद ने ग्राम सहकारी समितियों के हक में फैसला किया । राष्ट्रीय कांग्रेस ने तो निश्चय रूप से उनका समर्थन किया । राष्ट्रीय विकास परिषद ने अपनी हाल

की बैठक में फिर इस विषय में विचार किया और एक उप-समिति नियुक्त की, जिसने अपनी रिपोर्ट दे दी है।

अब हालत यह है कि ये व्यापक सिद्धान्त पूरी तरह मान लिये गए हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये उसूल ये हैं कि सामाजिक एकता हो और इन सहकारी संस्थाओं पर अफसरों का प्रभुत्व न हो। हा, अफसर मदद जरूर कर सकते हैं। राज्य, जहां तक मुमकिन हो, उनके गेयर (हिस्से) खरीदकर उनकी आर्थिक मदद न करे।

### आदिम जाति क्षेत्र

यह कह लेने के बाद कुछ अपवादों की भी गुजाइश है। एक बड़ा और लाजमी अपवाद आदिम जाति क्षेत्रों के सम्बन्ध में है। हम सख्ती के साथ ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते, जो शेष भारत के लिए तो ठीक हो, लेकिन, आदिम जाति क्षेत्रों के लिए नहीं। इसलिए आदिम जाति क्षेत्रों में उनकी परिस्थितियों के अनुरूप सहकारी समितियां बनायेंगे, क्योंकि उनमें मजबूत जातीय भावनाएं और संगठन होते हैं और हमारी सहकारी समितियां जरूर उनके अनुरूप होंगी।

आदिम जाति क्षेत्रों की तरह भारत में और पिछड़े क्षेत्र हैं और समस्या यह है कि हम उनके लिए उसूल में ढिलाई करें या नहीं। इस बारे में कुछ अलग-अलग राये हैं। एक अर्थ में, भारत का २० फीसदी हिस्सा पिछड़ा हुआ है। आखिर यह ऐसा सवाल नहीं है कि जिसपर केवल सिद्धान्त की दृष्टि से चर्चा की जा सके। हमें हर पहलू को देखकर फैसला करना होगा और यह सिद्धान्त ध्यान में रखना होगा कि हमें जहां



तक हो, छोटी सहकारी समितियाँ और उनके बड़े संघ कायम करना है ।

लाजमी है कि खुद राज्य सरकार को यह फैसला करना होगा कि किस जगह उसूल को ढीला करना है। उनकी जिम्मेदारी है और उन्हें ही फैसला करना होगा। लेकिन दूसरे सवाल के बारे में, जैसेकि राज्य की हिस्सेदारी का सवाल है, हम जैसे-जैसे समस्याएँ पैदा होगी, वैसे-वैसे विचार करेंगे। हम हमेशा उन्हें कुछ लचीलेपन से हल करने की कोशिश करेंगे। आखिरी नतीजा यह है कि राज्य के अधिकारी विचार करेंगे और फैसला करेंगे।

इस विषय में एक और समस्या है। इससे पहले अनेक मर्तबा यह कहा गया है कि सहकारिता कानून को सरल बनाया जाय। उसे सरल बनाया जा रहा है। हमें पता चला है कि कानून को आसान बनाने के साथ-साथ दरअसल कानून के परिपालन को सरल बनाने की जरूरत है। हमें पक्का यकीन है कि सहकारी सगठनों का सरकारी रूप खत्म होना चाहिए और अगर वे चाहे तो उन्हें गलती करने की आज़ादी होनी चाहिए।

## प्रशिक्षण और कुशलता

अब एक बहुत गम्भीर कठिनाई उठ खड़ी होती है। सहकारी समितियों के संचालन में प्रशिक्षण और कुशलता की जरूरत होती है। बेशक, सगठक को काफी प्रशिक्षित और कुशल होना चाहिए। ग्राम सहकारी समिति के सचिव या सेक्रेटरी भी कुछ प्रशिक्षित होने चाहिए, मामूली हिसाब-किताब

रखने की कला उन्हें आनी चाहिए। यह कहते हैं ~~नहीं~~। कभी-कभी सारे गांव में एक भी आदमी यह काम जानने-वाला नहीं मिलेगा। हम उन्हें थोड़ा-थोड़ा करके बड़ी सख्या में प्रशिक्षित करेंगे। मेरे खयाल से मही बात यह होगी कि दो आदमी इस काम को करनेवाले हों। एक ग्राम-सेवक और दूसरा ग्राम-शिक्षक। ग्राम-सेवक इस समय दस गांवों की सेवा करता है और वह पन्द्रह या दस या इससे भी कम सहकारी समितियों का काम देखे, यह उसके लिए भारी पड़ेगा। ग्राम-सेवक की कल्पना सामुदायिक विकास-ग्रान्दोलन में पैदा हुई। वह इस ग्रान्दोलन का हिस्सा है और उसे इसकी शिक्षा मिली है। मेरा खयाल है, करीब ३०,००० से ४०,००० ग्राम-सेवकों को प्रशिक्षित किया गया है। जायद उन पर जिम्मेदारी ज्यादा है और हमें उसमें कमी करनी पड़ेगी। इनके दाद ग्राम-शिक्षक हैं। मेरा खयाल है कि सहकारी समिति के हिमाय-किताब का काम उसे सौंप दिया जाय। लेकिन इस सबके बारे में प्रयोग करके देखना होगा। यह समस्या उठ सकती है कि गांव में जरूरी ट्रेनिंग पाया ना पटा-लिखा एक भी आदमी न हो। फिर यह भी हो सकता है कि मुश्किल करने के लिए गांव में रुपये-पैसे की एकदम कमी हो।

उत्पादक योजनाओं के लिए ही दी जाय और सहकारी समितियों के हाथों में रुपये के उपयोग का फैसला न छोड़ा जाय।

मैं चाहता हूँ कि सदन इस प्रसंग में समस्या पर विचार करे। मैं यह कहने का साहस करता हूँ कि कभी-कभी गरमा-गरम वाद-विवाद के बावजूद कोई आदमी ऐसा नहीं निकलेगा, जो इस बुनियादी दृष्टिकोण से असहमत हो, क्योंकि कोई दूसरा दृष्टिकोण है ही नहीं। जैसा कि मैंने हाल में सदन के सामने यह सवाल पेश किया था, जमीन की बहुसंख्यक छोटी इकाइयों से निपटने का और दूसरा रास्ता क्या है? अगर आप उन्हें ज्यो-का-त्यो रहने देते हैं तो वे अपने घरों से कभी बाहर नहीं आ सकेंगी। उनमें थोड़ा सुधार हो सकता है, लेकिन वे अपनी चहारदीवारी से कभी नहीं निकल सकेंगी।

ज्योही आप जमीन की समस्या के प्रति दृष्टिकोण में यह बुनियादी, मौलिक, परिवर्तन करते हैं, वैसे ही मेरा खयाल है कि उसके फलस्वरूप लाजमी तौर पर बराबर संयुक्त खेती को अपनाना होगा, जिसमें सदस्य अपनी जमीन के अलग-अलग हिस्सेदार बने रह सकते हैं।

अगर हम समस्या पर इस व्यापक दृष्टिकोण से, जो मैंने सदन के सामने रखा है, विचार करेंगे तो हम देखेंगे कि इसका सम्बन्ध सिर्फ खेती और कृषि से ही नहीं है, बल्कि वह हमको बड़े उद्देश्यों की ओर ले जायगा, धीरे-धीरे देहाती जिन्दगी के सारे ढाँचे को ही बदल देगा।<sup>१</sup>

---

१ सामुदायिक विकास और सहकारिता मन्त्रालय की अनुदान माग पर हुई बहस के दौरान लोकसभा में भाषण, १२ अप्रैल १९५६

## सहकारी संगठन के व्यावहारिक पहलू

नागपुर-प्रस्तावो ने एक गतिशील प्रक्रिया शुरू कर दी है। उनसे देश की और कांग्रेस संगठन की भी बड़ी सेवा हुई है, बशर्ते कि उनसे सहकारी आन्दोलन को जो गति मिली है, उसके साथ हम बराबर आगे बढ़े और कुछ काम करे।

यह मानी हुई हकीकत है कि सहकारी खेती की जगह लेने-वाली और कोई चीज ही नहीं है। हम अब जिसकी चर्चा कर रहे हैं, उसका फैसला तो हो चुका है। अब हमे व्यौरा तय करना है कि उस कार्यक्रम पर किस तरह अमल किया जाय और सहकारिता के अमली पहलुओं को तय करना है।

हम इस विषय पर विविध दृष्टियों से विचार करते आ रहे हैं। मेरा ख्याल है, आप सहमत होंगे कि अब उसके दर्शन अथवा मुख्य सिद्धान्तों की चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल, मेरे ख्याल से इसकी कभी भी जरूरत नहीं थी, कारण यह बात इतनी साफ है।

नागपुर-प्रस्ताव के बाद कुछ विरोध हुआ। वह बहुत ज्यादा तो नहीं था, लेकिन उसका स्वर तेज था और इसलिए उसकी ओर ध्यान गया। यह अच्छा हुआ, नहीं तो होता यह है कि अधिकतर लोग चुपचाप मान लेते हैं। दो-तीन महीने बाद यह मामला भी तय हो गया।

अब हम सहकारी खेती के व्यावहारिक पहलुओं की चर्चा कर रहे हैं, उसके सिद्धान्त या दर्शन की नहीं। यह कहा गया है कि नागपुर-प्रस्तावों के बाद से कांग्रेस-संगठन की बड़ी गति मिली है। यह एक दिलचस्प बात है, क्योंकि गायद कुछ खास कांग्रेसी आगकित थे कि इस प्रस्ताव से किसान, या कम-से-कम किसानों का एक वर्ग, नाराज हो जायगा।

असलियत यह है कि कुल मिलाकर इसका किसानों ने स्वागत किया है। यह सही है कि कुछ किसानों के दिमागों में कुछ सन्देह हैं, लेकिन मौटे तौर पर प्रस्ताव का पूरी तरह स्वागत हुआ है। आलोचना सयुक्त खेती के बारे में हुई है और दूसरे खास पहलू जाहिरा तौर पर पूरी तरह स्वीकार कर लिये गए हैं।

### दृढ़ किन्तु कड़ा नहीं

इस समस्या के प्रति हमारा दृष्टिकोण दृढ़ है, किन्तु कड़ा नहीं है। मैं सयुक्त खेती के बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, हालांकि हमने अपने मूल प्रस्ताव में सयुक्त खेती के लक्ष्य पर जोर दिया है। साथ ही, हमने यह भी कहा था कि फिलहाल हमें सेवा सहकारी संगठनों पर जोर देना है। इसकी दो विरोधी-से रूपों में व्याख्या की गई है। कुछ लोगों को अचरज हुआ है कि हमने सयुक्त खेती को तीन साल के लिए स्थगित कर दिया। दूसरे लोग सोचते हैं कि सयुक्त खेती तुरन्त शुरू होनेवाली है और अपने साथ घोर तबाही लानेवाली है।

दोनों ही मेरे खयाल से गलत हैं। हमारे लिए यह सोचना व्यावहारिक नहीं होगा कि हम तीन साल सेवा सह-

कारी संगठनों पर जोर दे और उसके बाद संयुक्त खेती की शुरुआत करें। आप इन कामों को अलग चौखटों में बांटकर नहीं कर सकते। हमें पूरी तस्वीर अपने सामने रखनी होगी। हालांकि हमारा फिलहाल जोर सेवा सहकारी सगठनों पर है, लेकिन जहाँ हालात अनुकूल हों, वहाँ संयुक्त खेती की भी शुरुआत कर सकते हैं।

सहकारिता आन्दोलन का मूल तत्त्व उसका स्वेच्छिक रूप है। हमें लोगों को अमली प्रयोग करके यकीन दिलाना होगा। हमें लोगों को दिखाना होगा कि सहकारिता कितनी कामयाब हो सकती है। दूसरी अहम बात यह है कि हमें सेवा सहकारी समितियों और संयुक्त खेती को जुदा नहीं करना चाहिए।

एक बोलनेवाले ने ऋण का सवाल उठाया और जुदा-जुदा अनुमानों के आधार पर यह जाहिर किया कि इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए बहुत धन की जरूरत होगी। हा, यह तो जाहिर है। अगर हम देश की आबादी, किसानों की संख्या और ऋण का हिसाब लगायें तो जरूर ही बहुत बड़ी रकम बनेगी। लेकिन किसान केवल ऐसे ऋण-उपभोक्ता ही नहीं होंगे, जो कुछ भी पैदा नहीं करते।

### ऋण और उत्पादन का योग

कुछ रूपों में वर्तमान प्रणाली पुरानी बनिया-प्रणाली जितनी भी संतोषजनक नहीं है। बनिया किसान की जमीन हड़प सकता था और एक बुरा सामाजिक तत्त्व था, लेकिन किसान की जरूरत के समय वह उसकी सेवा करने को तैयार

रहता था । किसान उसकी मदद ले सकता था, हालांकि फसल के समय बुनिया अपनी हालत का पूरा फायदा उठा सकता था । मौजूदा प्रणाली में किसान को चक्कर-पर-चक्कर काटने होते हैं और जब कर्ज मिलता है तो बहुत देर हो चुकती है । आज बड़ा किसान कहीं ज्यादा ऋण प्राप्त कर सकता है और दरअसल अपनी जरूरत से ज्यादा पा भी लेता है, कारण, वह बड़ी जमानत दे सकता है । हम गरीब किसान के लिए ऋण का कैसे प्रबन्ध करें, जिसके पास जमानत देने को कुछ नहीं है । और वही ऐसा आदमी है, जिसे अधिक पैदा करने के लिए मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है । फिर भारत में उसकी संख्या ही सबसे ज्यादा है ।

यह उसूल हमेशा याद रखना होगा कि ऋण उत्पादन के लिए दिया जाय । जहां तक मुझे मालूम है, ऋण जमानत की बुनियाद पर दिये गए हैं और इसलिए उनसे थोड़े लोगों ने ही फायदा उठाया है ।

किसानों में, खासकर छोटे किसानों में, कुव्यवस्था की आदत है । आप उसे जो ऋण देते हैं, वह उसे उत्पादक योजनाओं के बजाय दूसरे कामों पर खर्च कर सकता है । इसलिए यह जरूरी है कि ऋण का उत्पादन के साथ सम्बन्ध जोड़ दिया जाय । केवल इसी तरह हम ऋण की वापस वसूली कर सकेंगे ।

खेती की पैदावार बढ़ाये बिना हमारी सब पांचसाला-योजनाएं नाकामयाब होंगी, क्योंकि हमारे सब कामों में वह बुनियादी चीज है । मेरे खयाल से अब हरकोई यह महसूस करता है । कुछ समय पहले तक इसे महसूस नहीं किया जाता

था, इसीलिए राज्यों में कृषि-विभाग साधारणतया सहायक और दूसरे दर्जे के और कम महत्वपूर्ण समझे जाते थे।

आज हमारे सामने जो कठिन समस्याएं हैं, उनको देखते हुए कृषि-विभाग राज्य सरकार का सबसे महत्वपूर्ण विभाग समझा जा सकता है।

## वैज्ञानिक खेती

खेती की पैदावार हमारी बुनियादी समस्या है। वही हर बात की कसौटी होनी चाहिए। हमारे कृषि-विभागों में अच्छे विशेषज्ञ और अफसर हैं, लेकिन मुझे अक्सर यह सोचना पड़ता है कि अच्छे होते हुए भी वे बीते हुए कल के अर्थ में अच्छे हैं, आज के अर्थ में नहीं और आनेवाले कल के अर्थ में तो और भी कम अच्छे हैं।

वे बीते कल की निश्चित परिभाषा में सोचते हैं और उन्हें नये तरीके से डर लगता है। यह कोई अच्छी बात नहीं। यह सही है कि हमको विचारों में परम्परावादी होना पड़ता है और हम अचानक श्रंटशट योजनाएं शुरू नहीं कर सकते। लेकिन हमें बहुत ज्यादा परम्परावादी भी नहीं होना चाहिए। तरक्की की बुनियाद है परिवर्तन और आगे बढ़ना और दुनिया में खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए जो उल्लेखनीय बातें हो रही हैं, उनके साथ कदम मिलाकर चलना।

दूसरी दृष्टि से विचार करें तो हमें अपनी खेती को वैज्ञानिक बनाना है। जब मैं वैज्ञानिक खेती की बात करता हू तो मेरा मतलब औजारों से होनेवाली खेती से नहीं है। मैं यांत्रिक खेती के खिलाफ नहीं हू, लेकिन भारत की विशाल



आवादी को देखते हुए, मेरे खयाल से, वह यहा के लिए मौजू नही है ।

आप अभी काफी समय तक भारतीय खेती को यात्रिक रूप देने की बात नही सोच सकते । जबतक आप काफी आवादी को उद्योगो मे नही लगा देते, यह व्यावहारिक नही होगा । फिर भी मै यात्रिक खेती के अर्थ मे न सही, लेकिन वैज्ञानिक खेती के बारे मे जरूर सोचता हू ।

हम अपने मामूली किसान को, छोटे किसान को वैज्ञानिक खेती की बात समझा सकते है और इसमे मुझे कोई बुनियादी कठिनाई नजर नही आती । भारतीय किसान काफी भला है, बशर्तेकि हम उसके पास ठीक ढग से जाय । बेशक, वह परम्परावादी है, किन्तु इतना परम्परावादी नही कि ठीक ढग से समझाने पर बदल ही न सके । मनुष्य के रूप मे वह और स्थानो के किसानो जितना ही अच्छा है ।

अचरज की बात है कि ग्राम ऋण सर्वेक्षण समिति यह मानकर चली कि हमारे देहाती इतने पिछडे हुए है या झग-डालू है या आपस मे लडते रहते है कि आप उनपर भरोसा नही कर सकते । इसलिए उसने छोटी सहकारी समितियो का विरोध किया और बडी सहकारी समितियो की हिमायत की । उसका सारा दृष्टिकोण किसानो के प्रति अविश्वास और इस मान्यता पर आधारित था कि वे अयोग्य है । अगर भारतीय किसान सचमुच ऐसा है तो कैसी भी योजनाए बनाई जाय, वे जरूर नाकामयाब होगी । मै यह विचार स्वीकार नही करता । हमे अपने किसान को खेती के मामले मे अधिक वैज्ञानिक बनाना है और जिस हद तक वह अधिक वैज्ञानिक बनेगा,

उस हद तक वह कामयाब होगा और हम कामयाब हो सकेंगे।

हमें करना क्या है ? प्रशिक्षण जरूरी है। इन बातों का इतना जाम सहकारी समितियों जैसी संस्थाओं के जरिये ज्यादा आसानी से किया जा सकता है। मैं और कोई तरीका नहीं सोच सकता।

इसलिए भी सहकारी समितियां जरूरी हो जाती हैं। सहकारी संगठन सामाजिक संगठन का उच्च रूप है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं नहीं समझता कि कोई इस सिद्ध और प्रकट तथ्य को मानने से कैसे इन्कार कर सकता है। मैंने अक्सर पूछा है कि और कोई उपाय पेश किया जाय, लेकिन आलोचक चुप रहे।

कांग्रेस कार्यसमिति सौ आदमियों को प्रशिक्षित करना चाहती है, जो दूसरी जगह प्रशिक्षित केन्द्रों का काम सम्हाल सके। हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकारें और केन्द्रीय सरकार बहुत बड़ी तादाद में लोगों को प्रशिक्षण देंगी, किन्तु ऊपर बताये काम हम अपनी संस्था की ओर से करना चाहते हैं। हम इसके लिए सरकार पर ही निर्भर नहीं रहना चाहते। किसी भी दल को महज सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वह उसका पुच्छल्ला या सहारागीर बन जायगा। यह बात उस संगठन के लिए भी अच्छी नहीं है, जो सरकार को चलाता है।

यह जरूरी है कि हम अपने माध्यमिक स्कूलों में सहकारिता का विषय सरल रूप में दाखिल करें, ताकि वह बुनियादी प्रशिक्षण का अंग बन जाय।

## वर्तमान स्थिति

इस समय १,२०,००० सहकारी समितियों में से आधी काम नहीं कर रही है। आधी इस तरह काम करती है कि उसमें हेर-फेर करना होगा। मौजूदा स्थिति इतनी कमजोर नहीं है कि हम तरक्की न कर सकें। अगर ५०,००० सहकारी समितियाँ भी हो तो काम शुरू करने के लिए काफी होगी। अगर सन् १९५६ में एक भी नई सहकारी समिति स्थापित नहीं होगी तो मैं परवा नहीं करूँगा, हालाँकि मैं चाहूँगा कि नई सहकारी समितियाँ कायम हों।

इस समय का उपयोग लोगों को सहकारी समितियों का महत्व समझाने में किया जा सकता है। हर किसान-कुटुम्ब को सहकारी समितियों का महत्व समझाया जाना चाहिए। वर्तमान प्रगति इसलिए काफी नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्रशिक्षित आदमियों की कमी है, इसलिए नहीं कि लोग यह तरीका अपनाने में हिचकते हैं।

यह जरूरी है कि राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार प्रशिक्षण योजनाएँ हाथ में लें। कांग्रेस को भी अपनी दृष्टि से प्रशिक्षण का काम हाथ में लेना चाहिए। अगर हम यह नहीं करते और अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित नहीं करते तो उनके दिमाग योजना के अनुरूप नहीं बनेंगे और वे कोरमकोर रहेंगे। हमें मण्डलों के कार्यकर्ताओं को सरकारी प्रशिक्षण शिविरों में शामिल होने के लिए प्रेरित करना चाहिए। एक गाँव के लिए एक सहकारी समिति बनाई जाय, हालाँकि अगर गाँव छोटे हों तो वहाँ और पिछड़े क्षेत्रों में दो या तीन गाँवों को एक सहकारी संगठन में शामिल किया जा सकता है।

यह सवाल कभी-कभी पूछा जाता है कि कोई आदमी सहकारी संयुक्त खेती संस्था में शामिल होता है तो क्या उसे बाद में उससे अलग होने की इजाजत होगी ? दो-तीन शर्तों के साथ उसके अलग होने में कोई कठिनाई नहीं होगी ।

एक शर्त यह होगी कि किसीको भी अपनी मन की मौज के अनुसार सहकारी समिति में शामिल होने या निकल जाने की छूट नहीं होनी चाहिए । एक निश्चित समय की, मिसाल के लिए तीन बरस की, मियाद होनी चाहिए और उसके पहले किसीको सहकारी समिति से निकलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए । बेशक, अगर सदस्य को मुआवजे से सतोष है तो उसके निकलने में कोई कठिनाई नहीं होगी । कठिनाई तब आयगी जब वह अपनी जमीन वापस लेना चाहेगा । यह कल्पना की जा सकती है कि सहकारी समिति की किनारे की जमीन लौटा दी जाय, लेकिन बीच की जमीन नहीं लौटाई जा सकती । पर मैं कोई पक्का उत्तर नहीं दे सकता । हम कड़ा रुख नहीं अपनाना चाहते । जो आदमी हटना चाहे, उसे, जहां तक मुमकिन है, अच्छी-से-अच्छी शर्तों पर हटने दिया जाय । लेकिन उसे गड़बड़ी फैलाने या शरारत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती ।<sup>१</sup>

---

१ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, नई दिल्ली के भाषण से, १० मई १९५६

## अधिक अन्न-उत्पादन—एकमात्र कसौटी

सहकारी खेती पर हमला कांग्रेस के तमाम उसूलों और कार्यक्रमों को, जो आज़ादी के बहुत पहले से चले आ रहे हैं, सीधी चुनौती है। कांग्रेस का जो लक्ष्य है, यानी समाजवादी ढंग का समाज, और आप चाहे तो उसे समाजवाद भी कह सकते हैं, उस सबके यह खिलाफ है। इसलिए हमला वास्तव में व्यापक आधार पर है।

यह कहना बड़ा अजीब है कि सहकारी खेती सफल नहीं हो सकती और सहकारी खेती और सामूहिक खेती में कोई फर्क नहीं है। यह आश्चर्यजनक है कि जब बात ऐसी नहीं है तो इस प्रकार की बात कैसे कही जा सकती है, खासकर तब, जबकि हमने यह घोषित किया है कि देश के हालात को देखते हुए हम यहाँ सामूहिक खेती के कतई खिलाफ हैं। जहाँ-तक मेरा सम्बन्ध है, बात यहाँ खत्म हो जाती है। लेकिन आलोचक कहे चले जा रहे हैं कि सहकारी खेती और सामूहिक खेती एक ही चीज़ है। इस प्रकार के तर्क या कुतर्क का जवाब देना मुश्किल है।

आलोचक यह भी कहते हैं कि सहकारी खेती दबाव के बिना शुरू नहीं की जा सकती। हमने यह साफ़ कहा है कि यह पूरे तौर पर स्वेच्छिक आन्दोलन है। अगर किसान चाहे

तो उसमें शामिल हो, न चाहे तो न हो। यही नहीं, हमने कहा है कि वे सहकारी संगठन से अलग होना चाहे तो अलग भी हो सकते हैं। फिर भी अगर लोग कहे जाते हैं कि यह लाजमी है तो मैं क्या कर सकता हूँ ?

हमें यह याद रखना चाहिए कि सहकारी खेती ग्राम-सहकारिता का एक पहलू है। इस समय हमारा सारा जोर सेवा सहकारी संस्थाओं पर है। आप देखेंगे कि सहकारिता के आलोचक यदा-कदा कहते हैं कि वे सेवा सहकारी सभितियों के विरुद्ध नहीं हैं—यही आज हमारा खास कार्यक्रम है—बल्कि इस खतरनाक चीज सहकारी खेती के खिलाफ है, जो सामूहिक खेती का रूप ले लेगी और जो रसातल या नरक को ले जानेवाली है। मौजूदा हालत को समझे बिना, हमारा मकसद क्या है और हम किस उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, यह सोचे बिना वे एक ऐसी चीज की चर्चा करते जा रहे हैं, जिसकी रचना उन्होंने खुद अपने दिमागों से कर ली है। बेशक, निजी तौर पर मैं यह सोचता हूँ कि सहकारी संयुक्त खेती मुनासिब है, क्योंकि यह काम ज्यादा ऊँचा, ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन महज मेरे चाहने से यह नहीं हो जानेवाला है। वह होगा तभी, जब किसान खुद उसे अपनाने को राजी होंगे।

## किसानों की प्रतिक्रिया

मेरा खयाल है कि आमतौर पर भारत में किसान इस बारे में बहुत अनुकूल दृष्टि से विचार कर रहे हैं। मैं उस दिन सोनीपत गया हुआ था। सारे पंजाब के पंचों और सरपंचों

की बड़ी कान्फ्रेंस थी। शायद छहसौ या एक हजार से ज्यादा उनकी सख्या रही होगी। मैंने उनसे कहा, “मैं आपके सामने कोरा भाषण नहीं देना चाहता। इसके बजाय मैं यह जानना चाहूँगा कि आप क्या महसूस करते हैं?” मैंने उन्हें बातें करने दी और उन्होंने बातें की भी। मुझे यह जानकर ताज्जुब हुआ कि वे न सिर्फ दो दिन से सहकारी खेती की चर्चा कर रहे थे, बल्कि इस नतीजे पर पहुँच चुके थे कि यह अच्छी चीज है और उसे उन्हें अपनाना चाहिए। मुझे उठकर उन्हें समय से काम लेने के लिए कहना पड़ा। मैंने कहा, “जल्दी न करे। खाली जोश काफी नहीं है। आपको पहले उसका प्रशिक्षण लेना होगा। पहले सारी बातों को समझ ले। धीरे चले।” मुझे रफ्तार को धीमा करने का काम करना पड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि महज दिखावे के लिए कुछ किया जाय। मैं कामयाबी से चलनेवाले फार्म चाहता हूँ। उसके लिए प्रशिक्षण और प्रशिक्षित आदमियों की जरूरत होगी और हम उन्हें हजारों की तादाद में प्रशिक्षित कर रहे हैं।

जाहिर है कि कोई भी विचार-धारा, जो अन्न की पैदावार में रुकावट डालती है, बुरी है। किसी भी विचार-धारा का पूरा मकसद यह होना चाहिए कि उसके नतीजे निकले। यह कोई निर्वाण प्राप्त करने जैसा आध्यात्मिक सवाल नहीं है, जिसकी कोई परीक्षा नहीं की जा सकती। यहाँ कसौटी यह है कि अधिक अन्न की पैदावार हो। यही सच्ची कसौटी है।<sup>१</sup>

: १४ :

## कमज़ोर याददाश्त

सहकारिता के बारे में पिछले महीनो की चर्चा का अधिकांश भाग मददगार नहीं रहा, क्योंकि उसमें सिद्धान्त-वादिता और दलीलबाजी ज्यादा थी, खासतौर पर संयुक्त अथवा सहकारी खेती का सवाल कुछ लोगों के लिए चिन्ता का विषय रहा, हालांकि आज हमारे सामने यह पहला सवाल नहीं है।

कुछ लोग इस गलत धारणा के शिकार हैं कि इस समय ग्राम सहकारी समितियों और सहकारी खेती पर जो जोर दिया जा रहा है, यह कोई बिल्कुल नई बात है, पिछली नीति को बदला जा रहा है। इस कुशका का कारण यही हो सकता है कि इन लोगों को पिछले सालों के घटना-क्रम का पता नहीं है।

सहकारिता की पूरी कल्पना राष्ट्रीय कांग्रेस में एक पीढ़ी से या इससे भी ज्यादा समय से रमी हुई है। दर-असल, लम्बे समय पहले भारत में सहकारी राष्ट्र का निर्माण कांग्रेस का ध्येय निर्धारित किया गया था। सहकारी राष्ट्र के स्वरूप के सम्बन्ध में गायद मतभेद हो सकता है, किन्तु गांधीजी ने अक्सर गांवों में सहकारिता के बारे में और सहकारी खेती के बारे में भी लिखा और बोला है। पिछले समय



मे विनोबाजी ने भी ऐसा ही किया है ।

लेकिन मामूली भाषणों और लेखों के अलावा कांग्रेस की नीति कांग्रेस के सन् १९४५, १९५१ और १९५७ के चुनाव-घोषणा-पत्रों में निर्धारित की गई है । हर आदमी को यह हक हासिल है कि इस नीति से सहमत हो या असहमत हो, पर कहने का मतलब यह है कि यह नई नीति नहीं है, जिसे अचानक देश पर थोपा गया हो । यह उतनी ही पुरानी है, जितनी कि गांधीजी के नेतृत्व में बनी कांग्रेस, और इसे आम चुनावों के समय तीन बार मतदाताओं के सामने रखा गया है । यह अचरज की बात है कि लोगों की याददाश्त इतनी कमजोर है कि वे इसे भूल गये हैं ।

हमारा तात्कालिक लक्ष्य भारत के सभी गांवों में सेवा सहकारी समितियाँ कायम करना है । मैं उम्मीद करता हूँ कि धीमे-धीमे भविष्य में इसके फलस्वरूप सहकारी खेती गुरु होगी । लेकिन यह अगला कदम है । यह याद रखना होगा कि सहकारिता का मुख्य तत्त्व स्वेच्छिक सहयोग है । सहकारिता को ऊपर से नहीं थोपा जा सकता ।

मैं सहकारी सस्थाओं के लिए प्रशिक्षण की बुनियादी जरूरत पर जोर देता आ रहा हूँ । सहकारी सस्थाओं को चलाने के लिए जबतक प्रशिक्षित कार्यकर्ता नहीं होंगे तबतक दुनिया-भर के जोश-खरोश से भी काम बननेवाला नहीं है । सिर्फ ऊँची किस्म के शिक्षण की ही जरूरत नहीं है, बल्कि पंचों और सरपंचों को सीमित प्रशिक्षण भी देना होगा ।

ऋण देने के लिए उपलब्ध साधनों की भी काफी चर्चा

है। कुदरतन यह जरूरी है, लेकिन मुझे पता है कि गुजरे जमाने में उपलब्ध साधनों का भी पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ। मैं नहीं सोचता कि इस काम के लिए साधनों की वाकई कमी होगी। आज जरूरत इस बात की है कि ठीक ढंग का प्रशासनिक तंत्र हो। यदि यह तंत्र और प्रशिक्षित कार्यकर्ता उपलब्ध हो तो मुझे शक नहीं कि साधन भी उपलब्ध होंगे। नकली सहकारी संस्थाएँ बनने या जालसाज आदमियों द्वारा सहकारिता के नाम का खुदगर्जी के लिए इस्तेमाल करने की वृत्ति रही है और बेशक, आगे फिर वैसा ही होगा। इससे सावधान रहना होगा।

मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कांग्रेस कुछ बड़े सवालों पर जोर देगी और आइदा काम के लिए मजबूत नींव रखेगी।<sup>१</sup>

---

१ मैसूर में आयोजित राज्यों के सहकारी मंत्रियों की कांग्रेस को सदेश, २८ जुलाई १९५६

## एकमात्र दृष्टिकोण

करीब एक चौथाई सदी पहले भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त कृषि शाही कमीशन ने कहा था कि भारत में सहकारिता के अलावा कृषि के लिए कोई भविष्य नहीं है। मैं इस कथन से पूरी तरह सहमत हूँ। यह जाहिर ही है कि सहकारी तरीका न केवल खेती के लिए, बल्कि और कामों के लिए भी सही तरीका है। दूसरे देशों में, चाहे वे पूँजीवादी, समाजवादी या साम्यवादी हों, सहकारी आन्दोलन ने बड़ी प्रगति की है। मेरे खयाल से वक्त आ गया है जब भारत में इस आन्दोलन को बढावा देने और आगे बढाने की पूरी कोशिश की जाय।

जैसाकि उसके नाम से ही जाहिर है, सहकारिता एक स्वेच्छिक प्रयास है। दबाव का कोई भी तत्त्व सहकारिता के वास्तविक स्वरूप को नष्ट कर देगा।

इस आन्दोलन से उसके सदस्यों को तो फायदा होता ही है, इसके अलावा वह श्रेष्ठतर समाज-संगठन का रूप है।<sup>१</sup>

---

१ अखिल भारतीय सहकारिता सप्ताह के लिए सदेश, ६ नवम्बर १९५६

: १६

## सहकारी खेती

मैं मानता हू कि सहकारी खेती जाहिरा तौर पर भारत की जरूरतों को पूरा करेगी। जब मैं भारत की जरूरतों की बात करता हू तो मैं कोई सैद्धान्तिक प्रस्ताव पेश नहीं करता, क्योंकि हर देश की जरूरतों का अलग से विचार करना होगा और हम कोई निश्चित नुस्खा लागू नहीं कर सकते। भारत में जमीन की इकाइया बहुत छोटी हैं। एक एकड़, दो एकड़ या इससे कुछ ज्यादा हो सकती है, लेकिन आमतौर पर एक एकड़ से कम ही होती है। एक या दो एकड़ का मालिक कोई वास्तविक प्रगति कर सकेगा, यह आशा नहीं की जा सकती। अगर कोई ऐसा कर लेता है तो वह बहुत चतुर आदमी होगा। लेकिन यह अलग विषय है। इसलिए यह लाजिमी हो जाता है कि छोटे किसान सहकारी तरीके पर संगठित हो और इस तरह कुछ हद तक बड़े पैमाने की खेती और अधिक साधनों का फायदा उठाये।

जैसाकि सदन को पता है, यह टैगोर शताब्दी का साल है और मैं रवीन्द्रनाथ ठाकुर का एक भाषण पढ़ रहा था, जो उन्होंने एक राजनैतिक कांग्रेस में, बंगाल में, मेरे खयाल से सन् १९०७ या १९०८ में, दिया था। शायद यह पहली और एकमात्र राजनैतिक कांग्रेस थी, जिसमें उन्होंने

भाषण दिया। यह बंगाल की राजनैतिक कान्फ्रेंस थी और मुझे खुशी हुई और ताज्जुब हुआ कि उस भाषण में बंगाल के लिए और ग्रेप भारत के लिए सहकारी खेती को अपनाने का दिल से अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा, हमारे लिए यह युक्तियुक्त और अनिवार्य है कि हम सहकारी खेती को अपनाये। उनकी इसके पक्ष में दलील यह थी कि भारत ने जमीन की इकाइया बहुत छोटी हैं। मैं भी यही मानता हूँ, लेकिन हम इस तरह आगे बढ़ रहे हैं कि हमें फिलहाल सेवा सहकारी सनितियाँ कायम करने पर जोर देना चाहिए, कारण सवाल किसी काम को करने का फैसला करने का नहीं है। पहले लोगो को उस काम का तरीका सीखना होगा, यह सबसे जरूरी बात है। जहाँ प्रशिक्षण का अभाव था, सहकारी सस्थाएँ नाकामयाब हो गईं। सेवा सहकारी सस्थाओं के लिए भी काफी शिक्षण और प्रशिक्षण की जरूरत होगी। यह पहला कदम है। अगर इसे कामयाबी से उठा लिया तो अगला कदम आसान हो जायगा।<sup>१</sup>

---

१ राज्य सभा में तीसरी योजना पर दिये भाषण में, २६ अगस्त १९६१

## आपसी आदान-प्रदान का तरीका

करीब छः दिन पहले मैं बम्बई में था और मुझे महाराष्ट्र कोआपरेटिव बैंक के स्वर्ण जयन्ती समारोह में भाषण देने के लिए निमन्त्रित किया गया। कुछ तथ्यों से मैं काफी प्रभावित हुआ। पहले, बैंक के विकास और प्रगति के इतिहास से। दूसरे, उसके कार्यकाल में सरकारी आदमियों का उसके साथ इतना सम्बन्ध नहीं रहा, जितना सार्वजनिक लोगों का। मुझे सब आदमियों के नाम याद नहीं हैं, किन्तु एक नाम अच्छी तरह याद है और वह है श्री गोपालकृष्ण गोखले का। यह काम निश्चित रूप से गैर-सरकारी प्रवृत्ति के रूप में शुरू किया गया। बेशक, सरकार ने थोड़ी मदद दी, हालांकि देश की पुरानी अंग्रेज सरकार ने बहुत बार उसकी मदद नहीं की या उसे नियंत्रित करने की कोशिश की। मैं इसपर जोर देना चाहता हूँ कि सरकारी नियंत्रण से ज्यादा नुकसानदेह दूसरी बात नहीं हो सकती। वह मौत को चुपटाने के समान है।

सहकारिता सरकारी नियंत्रण नहीं है। अगर कोई सरकारी नियंत्रण है, अच्छा या बुरा तो वह सहकार नहीं होगा, और कुछ भले ही हो। हमें इस बारे में बिल्कुल साफ होना चाहिए। अगर आप भारत की मौजूदा परिस्थितियों की पड़ताल करें तो आपको यह सचाई जाहिर हो जायगी। जहाँ

गैर-सरकारी लोगों ने पहल की और इस काम में लगे, वहाँ आन्दोलन फला फूला है और जहाँ सरकार ने एक तरह से उसका पोषण किया वहाँ वह आगे नहीं बढ़ा। आमतौर पर यह ठीक नहीं कि जुदा-जुदा राज्यों के काम की तुलना की जाय, लेकिन इस मौके पर अलग-अलग राज्यों की प्रगति का लेखा-जोखा करना लाभदायक होगा। सामुदायिक विकास-मंत्री ने इस विषय में हमें कुछ बताया है। भारत के चार राज्य सहकारी आन्दोलन में अगुआ हैं। यह कोई आकस्मिक चीज नहीं है, बल्कि उसके पीछे गुजरे जमाने का काम है। लोगो ने इसका निर्माण किया है, सरकार ने नहीं। मैं फिर कहता हूँ और बराबर कहता रहूँगा कि मैं सहकारी प्रयास के साथ सरकार के सम्बन्ध को नापसन्द करता हूँ। हाँ, सरकार रुपये-पैसे आदि से मदद कर सकती है।

### राज्यों की तस्वीर

सहकारिता के क्षेत्र में जिन चार राज्यों ने अच्छी प्रगति की है वे हैं—महाराष्ट्र, गुजरात, मद्रास और आंध्र प्रदेश। उनका काम सारे देश के काम के मुकाबले करीब आधा होगा। दूसरी श्रेणी में मैसूर और पंजाब आते हैं, जिन्हें सहकारिता के क्षेत्र में काफी प्रगतिशील राज्य कहा जा सकता है। तीसरी श्रेणी में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश और जम्मू तथा काश्मीर हैं, जो ऊपर बताये राज्यों से तो पीछे हैं, लेकिन कमोबेश सही दिशा में जा रहे हैं। चौथी श्रेणी में, जहाँ तक सहकारी आन्दोलन का सम्बन्ध है, गति-रहित और स्थिर अथवा मरणशील राज्य हैं उड़ीसा, बिहार, पश्चिमी

बंगाल और असम । इन राज्यों में प्रगति करने के बजाय यह आन्दोलन पिछड़ा है । इससे यह जाहिर होता है कि इन चार राज्यों में सहकारी आन्दोलन को ठीक तरह से नहीं समझा गया है या उसमें दिलचस्पी नहीं ली जा रही है । बेशक, उनमें कांग्रेस और भाषण होते होंगे, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा और आन्दोलन को समझा भी नहीं गया । यह इतना तकलीफदेह है कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता । राज्यों की स्थिति में जो यह अन्तर है, उससे हमें सोचने की प्रेरणा मिलनी चाहिए ।

## सम्य समाज का प्रतीक

सहकारी आन्दोलन अनेक देशों में बहुत समय पहले निस्वतन्त्र सीमित पैमाने पर और सीमित उद्देश्यों से शुरू किया गया । हर देश में, चाहे वह साम्यवादी हो, समाजवादी या पूँजीवादी, उसका बड़ा विकास हुआ है और हो रहा है, क्योंकि उसने एक बड़ी जरूरत को पूरा किया है । अलग-अलग देशों में उसका गठन थोड़ा जुदा हो सकता है, लेकिन आन्दोलन की बुनियादी बातें सब जगह एक जैसी हैं । सहकारी संस्थाएँ हर क्षेत्र में हैं—कृषि में, उद्योग में, सेवाओं में और बहुत-से दूसरे कामों में वे हैं । शायद ही कोई ऐसी जगह होगी, जहाँ सहकारी भण्डार न हो, जो समाज को मुनासिब कीमतों पर चीजें मुहैया करता है । कीमतों को नियंत्रित करने का यह बहुत प्रभावशाली तरीका है । भारत में कीमतों के कारण, खासकर अनाज की कीमतों और बंटवारे के कारण काफी परेशानी है । उसका जाहिरा इलाज सहकार है ।



आप देखेंगे कि जहाँ कहीं देश के किसी हिस्से या किसी जिले में सहकारी आन्दोलन का काफी विकास हुआ है, वहाँ कीमतों पर कहीं ज्यादा नियंत्रण रहा है। लेकिन इस पहलू पर यहाँ दिल्ली जैसे बड़े शहर में भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। मुझे बताया गया है कि ऐसे छोटे सहकारी भण्डार हैं, जिन्हें आप कहीं उपवस्तियों में दूरबीन से ही देख सकते हैं। इस हालत पर मुझे ताज्जुब होता है क्योंकि आजकल सहकारी भण्डार सभ्य समाज की मामूली निशानी बन गये हैं।

सहकारिता कामों को कुशलता और किफायत से करने की विधि से कुछ और अधिक है। यह किफायत का न्यायोचित तरीका है। वह समानता लाता है और विषमता की बढ़ोतरी को रोकता है। लेकिन वह इससे भी कुछ गहरा है। यह जिन्दगी का एक तरीका है। वह निश्चय ही जीवन का पूजीवादी तरीका नहीं है, वह सौ फीसदी समाजवादी तरीका भी नहीं है, तो भी पूजीवाद को निस्वतः समाजवाद के भी कहीं ज्यादा निकट है। जो हो, यह जीवन का तरीका है और अगर हम उसका दायरा आर्थिक क्षेत्र से बढ़ा सकें, अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार में उसका प्रवेश करें तो यह आपसी आदान-प्रदान का तरीका हो सकता है। सहकार आपसी आदान-प्रदान है, आदान-प्रदान का एक तरीका है। वह अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र को बढ़ाने का तरीका है। हालाँकि हो सकता है कि यह शब्दावली बहुत ठीक न हो, लेकिन यह शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व का एक तरीका है। अगर लोग बातों पर सहकारी ढंग से विचार करें तो उनको लाजिमी तौर पर शान्ति के रास्ते पर जाना होगा, संघर्ष और युद्ध के रास्ते पर नहीं।

## पुराने जमाने की प्रणाली

उन्नीसवीं सदी और उसके आस-पास पूजीवाद ने प्रगति-शील देशों के आर्थिक उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति की। हमें इन प्रगतियों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। लेकिन यह सच है कि पूजीवादी समाज-व्यवस्था की बुनियाद में तेज होड़, भयंकर अर्थलोलुपता और संग्रह-वृत्ति है। उसमें राष्ट्र और राज्य जितनी ज्यादा तरक्की करता है, उतनी ही ज्यादा राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं बढ़ती हैं। दुनिया के मौजूदा हालात में मेरे खयाल से यह प्रणाली समय से पिछड़ी हुई हो गई है, क्योंकि हम ऐसी मंजिल पर पहुंच चुके हैं जब पूजीवादी तरीके से बिना एक दूसरे का गला काटे, बिना जंग या जंग जैसी किसी चीज के बांटने के लिए कुछ ज्यादा बाकी नहीं बचा है। उस जमाने में जब दुनिया के ज्यादातर भागों का शोषण करने की गुंजाइश थी, पूजीवादी व्यवस्था का विस्तार किया जा सकता था। किन्तु आज अगर हमें जिन्दा रहना है तो चाहे आदमी हो, कुनबा हो, देश हो या सारी दुनिया ही क्यों न हो, जीवन की समस्याओं के प्रति सहकारी दृष्टिकोण अधिकाधिक जरूरी होता जा रहा है, क्योंकि आज हम दुनिया में एक-दूसरे के बहुत पास, आदमियों से भरे समाज में ठीक उसी प्रकार रहते हैं, जैसे परिवार में और उसमें सहकार करना पड़ता है।

## तकनीकी प्रौढ़ता

अगर आप पूछें कि भारत में हमारा लक्ष्य क्या है तो इस सवाल के कई जवाब हैं। एक जवाब तो यह है कि हम तकनीकी प्रौढ़ समाज बनाना चाहते हैं। अगर हम किसी भी

कारण से तकनीकी दृष्टि से पिछड़ी हालत मजूर करते हैं तो हमें गा के लिए ऐसा नहीं करते । मिनाल के लिए भारत में हमें छोटे उद्योग, ग्राम-उद्योग रखने होंगे, लेकिन मैं इन उद्योगों का तकनीकी पिछड़ापन स्वीकार नहीं करता । मैं हर चीज के पिछड़ेपन को नापसन्द करता हूँ, चाहे वह पिछड़ापन तकनीकी हो, दिमागी हो या शारीरिक । हमें कार्यकुशल, योग्य आदमी चाहिए और अगर आपको ग्रामोद्योगों को रखना है—उन्हे इस देश में सामाजिक और दूसरे कारणों से अवश्य रखना होगा, तां इन ग्रामोद्योगों को भी ग्राम की सतह पर तकनीकी दृष्टि से, जहां तक मुमकिन हो उन्नत होना चाहिए । मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ कि कुछ लोग पिछड़ेपन को भी एक अच्छा गुण समझते जान पड़ते हैं । यह सद्गुण नहीं, वेवकूफी है । मैं वेवकूफी को नापसन्द करता हूँ । क्या किसी काम को दस हजार या पांच हजार सालों पहले जिस तरह किया जाता था, उसी तरह करने में कोई सद्गुण है ?

अगर जमीन की बहुत छोटी इकाइयाँ हैं तो सहकारी समितियों और संयुक्त खेती को अपनाये बिना इस देश में तकनीकी दृष्टि से खेती की प्रगति नहीं हो सकती । मैं कल्पना कर सकता हूँ कि एक बड़े जमींदार के एक बड़े कृषि-फार्म पर तकनीकी सुधार हो सकते हैं, लेकिन यह बुनियाद सामाजिक दृष्टि से बुरी है और सामाजिक समस्याएं पैदा करती हैं । यही कारण है कि हमने जमींदारों को खत्म कर दिया है । लेकिन उनकी जगह हमें सहकारी संस्थाएं खड़ी करनी होंगी, ताकि जमींदारी-प्रणाली की बुराई से दूर रहते हुए निस्वतन्त्र बड़े सावनों का लाभ उठाया जा सके ।

## उद्योग और जन-साधारण का विकास

कुछ राज्य केन्द्रीय सरकार से माग करते हैं कि उनके यहा बड़े उद्योग कायम किये जायं । वे अपने यहां बड़े-बड़े कल-कारखाने कायम करने को उत्सुक हैं । उनकी इस इच्छा की मैं आलोचना नहीं करता, उन्हें दोष भी नहीं देता, किन्तु यह सचाई है कि देश का औद्योगिक दृष्टि से आगे बढ़ा हुआ एक राज्य फी आदमी औसत आय की दृष्टि से सबसे पिछड़े राज्यों में है । बिहार को लीजिये । सहकारिता के क्षेत्र में बिहार अन्य राज्यों से बहुत पीछे है, हालांकि वह देश का अत्यन्त औद्योगिक भाग है । वहा उद्योगों पर खूब रुपया खर्च किया जा रहा है और विशाल योजनाएं अमल में लाई जा रही हैं । इसके विपरीत, पंजाब में अक्सर बड़े उद्योग नहीं हैं । लेकिन वह देश का बहुत खुशहाल राज्य है और वहां निजी आमदनी की सतह सबसे ऊंची है । कारण, उसकी कृषि की हालत मामूली तौर पर अच्छी है । वह खूब मेहनत करता है, उसमें छोटे-छोटे उद्योग हैं, ज्यादातर लोग डटकर काम करते हैं और इससे दरअसल आर्थिक प्रणाली को ताकत मिलती है । अगर आप समझते हैं कि बड़े कल-कारखानों से अचानक अन्तर पड़ जायगा तो आप गलती करते हैं । बड़े कारखाने का महत्व यह है कि वह बहुत सारे छोटे कारखानों, छोटे उद्योगों को जन्म देता है ।

यह जानना दिलचस्प होगा कि जमींदारी-प्रथा के नीचे रहा हुआ देश का ज्यादातर हिस्सा ऐसी हर बात में पीछे है, जिसमें सबकी कोशिश और सूझबूझ की आवश्यकता होती है । बेशक, सहकारिता में सबके प्रयास, गतिशीलता और

पहल की जरूरत होती है। छोटे उद्योगो वगैरा मे भी लोगो की पहल जरूरी है। उनमे आपको ऊँचे दर्जे के लोग, योग्य वैज्ञानिक और प्रोफेसर मिलेगे, लेकिन जमींदारी-प्रथा मे जन-साधारण पिछड़ा हुआ है। मेरे खयाल से उन्हे जमींदारी-प्रथा ने सैकड़ो सालो से पीड़ित किया है। बेशक, अब हमने उन्हे उससे छुटकारा दे दिया है, लेकिन सही छुटकारा तो तब होगा, जब उनके जीवन मे वह वसन्त आयगा, जो लोगो मे नया प्राण भर देता है। मेरे खयाल से इस पंचायतीराज के धन्धे का मुख्य उद्देश्य वह वसन्त लाना है, जो हमारे देहातियो को आत्मनिर्भरता और शक्ति लाँटायगा, जिन्हे जमींदारी-प्रथा और कुछ हद तक अन्य बातो ने इतने लम्बे समय से वंचित रखा था। अगर आप पंचायतीराज के साथ सहकारिता को जोड़ दे तो आप लोगो को ताकत बढानेवाली जरूरी दवा दे सकेगे, बशर्ते कि दोनो प्रयोग अच्छी तरह से चले।

हमारे लिए यह जरूरी है कि हम कुछ आकड़ो और तथ्यो के आधार पर देश की तरक्की का माप करे। मिसाल के लिए देखे कि कितने उद्योग कायम हुए है। लेकिन हमको देखना यह है कि जन-साधारण की हालत मे कितना सुधार हुआ है। देश के ४४ करोड लोगो का विकास होना है और उनके पास पंचायती राज, सहकारी संस्थाओ और इस प्रकार के दूसरे आन्दोलनो के जरिए पहुँचा जा सकेगा। मैने कही पढा है कि पंचायती राज ने सारे देश मे कोई १ करोड पंच पैदा कर दिये है। यह इतनी बडी सख्या है कि मेरे पावतले की मिट्टी ही खिसक गई। वास्तव मे यह सख्या २५ लाख है, फिर भी २५ लाख आदमियो के हाथो मे अधिकार और जिम्मेदारी का

पहुचना बहुत बड़ी बात है ।

मुझे उम्मीद है कि मैंने सहकारिता के बारे में अपनी दृढ़ भावनाओं से आपको परिचित कर दिया है । मेरे खयाल से यह हमारी कृषि के लिए, उद्योगों के लिए और इससे भी अधिक हमारी सारी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय जीवन-दृष्टि के लिए बुनियादी चीज है । बेशक, सरकार उसमें मदद देती है, पर यह सरकार-निर्देशित दिखावा नहीं है । ऐसा नहीं है कि बड़े-बड़े दफ्तरो में बड़े-बड़े अफसर बैठे हैं और बड़े चपरासी उन दफ्तरों के बाहर खड़े हैं और सारी चीज को संचालित और नियंत्रित कर रहे हैं । यह बिल्कुल आपत्तिजनक होगा । सहकारिता में आपसी आदान-प्रदान है, खानपान और भाई-चारे की भावना है—यह भावना कि कोई भी मामूली किसान बड़े अफसरों से डरे बिना उसमें भाग ले सकता है ।<sup>१</sup>

---

१ नई दिल्ली में आयोजित राज्यों के सहकारी मन्त्रियों के सम्मेलन में उद्घाटन भाषण से, ३० अक्टूबर १९६१

: १८ :

## अनुभव से सीखना

इन चुनावों में सयुक्त खेती के सवाल का खूब फायदा उठाया गया और वह भी काफी गलत तरीके से । लोग कहते फिरे, “तुम्हारी जमीने तुमसे छीन ली जायगी,” हालांकि यह बात बिल्कुल गलत है । मेरी यह दृढ़ मान्यता है कि भारत के आज के हालात में सयुक्त खेती मुनासिब है । उससे पैदावार बढ़ेगी और किसानों को फायदा होगा । हमने यह भी कहा कि बिना किसानों की सहमति के सयुक्त खेती नहीं होगी, किसान अगर पसन्द न करे तो सयुक्त खेती से दो-तीन साल बाद अलग हो सकेंगे और जमीन की मालिकी नहीं छीनी जायगी ।

जैसा कि मैंने दूसरी जगह कहा है, रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस के अध्यक्षपद से सयुक्त खेती की हिमायत की थी । क्यों ? उन्हें राजनैतिक समस्याओं, समाजवाद, साम्यवाद या ऐसी और किसी चीज से सरोकार नहीं था । उन्होंने सयुक्त खेती का इसलिए समर्थन किया था कि बंगाल के हालात को देखते हुए उसीके जरिए प्रगति की जा सकती है । इससे बड़ी बात यह कि उन्होंने अपनी जमींदारी में सयुक्त खेती शुरू की । फिर भी कुछ लोगों की यह गलत धारणा है कि ये कुछ नई कल्पनाएँ हैं, किसी भयंकर स्थान से आई हैं और भारत की पवित्र भूमि को भ्रष्ट कर देगी ।

हम कुछ निश्चित विचार लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं यह कहूंगा कि राष्ट्रपति ने ठीक ही कहा है कि इन चुनावों ने जाहिर कर दिया है कि जनता न सिर्फ हमारे व्यापक विचारों को, जिनका हम अनुसरण करना चाहते हैं, स्वीकार करती है, बल्कि उनसे पूरी तरह सहमत है और उनको बढ़ावा देना चाहती है। दरअसल ज्यादातर आलोचना विचारों की नहीं, बल्कि इस बात की थी कि उन विचारों पर अमल करने में देरी क्यों की जा रही है। हमारा रुख कड़ा और कट्टर सिद्धान्तवादी नहीं है। हमारे लक्ष्य के बारे में और उसे सिद्ध करने के तरीके के बारे में हमारे कुछ बुनियादी विचार हैं, किन्तु साथ ही हम व्यावहारिक दृष्टि रखते हैं। हम अनुभव से सीखते हैं और कष्टकर कदम उठाते हुए आगे बढ़ते हैं।

कोई भी सरकार, भारत में या और किसी जगह जनता की मदद के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। केवल सरकारी एजेंसी के जरिए इन बड़ी योजनाओं पर अमल नहीं किया जा सकता। हमें जनता से काफी मदद मिली है। साथ ही, हमको युगों की विरासत—इस देश की जड़ता और उससे सम्बन्धित बातों का सामना करना है।

सदन को याद होगा कि जब कुछ ग्रह एक-दूसरे के नजदीक आये थे तो सारे देश में कितनी भारी उत्तेजना जाहिर की गई थी और उस उत्तेजना को फैलाने में बहुत-से दलों के अनेक लोगो ने, जिनमें मेरा खयाल है, कांग्रेस पार्टी के लोग भी शामिल थे, योग दिया था। इस अप्टग्रह के प्रकोप को शान्त करने के नाम पर काफी रुपया, शक्ति और समय खर्च किये गए। यह वह हालत है, जिनका हम मुकाबला कर रहे



हैं। हम वास्तव में अन्धविश्वास से लड रहे हैं, चाहे वह कही भी जाहिर हो। कोई घटना होगी या नहीं, इससे मैं इन्कार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अन्धविश्वास का गिकार नहीं बनूंगा। मुझे और मेरी पार्टी को वोट मिले या न मिले, कुछ बातों पर हमें डटे रहना होगा। हमें राष्ट्र की समस्याओं के प्रति युक्तियुक्त, तर्कसंगत और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना होगा।<sup>१</sup>

---

<sup>१</sup> लोकसभा में राष्ट्रपति के भाषण पर हुई बहस के उत्तर से,  
१६ मार्च १९६२

: १६ :

## सेवा सहकारी समितियां

हमने कृषि पर बहुत ज्यादा जोर दिया है और उसमें सुधार दिखाई देने लगा है। सुधार हो रहा है, लेकिन उसकी गति ज्यादा तेज होनी चाहिए थी। हर सामुदायिक विकास खण्ड और पचायत को यह महसूस करना चाहिए कि कृषि का विकास उनका काम है, कारण उसीपर हर प्रकार की खुशहाली निर्भर करती है। कृषि में भी सहकारी समितियां शामिल हैं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि उनके बिना गांव तरक्की नहीं कर सकता। हमने सहकारी खेती की चर्चा की है और कुल मिलाकर मैं देखता हूं कि सहकारी फार्मों का भी काफी ठीक-ठीक विकास हुआ है, हालांकि उनकी सतह छोटी रही है, कारण उनपर हमने काफी जोर नहीं दिया। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप उनपर खास तौर पर जोर देते फिरे। हम हर जगह, जहां भी मुमकिन हो और लोग रजामन्द हों, सेवा सहकारी समितियां कायम करें। अगर आप एकदम सहकारी खेती शुरू करेंगे तो वह नाकामयाब होगी। आपको हमेशा भारत के हालात पर निगाह रखनी चाहिए। आप उसूल की बुनियाद पर फैसला न करें कि चूँकि एक बात रूस, अथवा अमरीका या इंग्लैण्ड के लिए अच्छी है, इसलिए भारत के लिए भी अच्छी होगी। यह उसूल लागू नहीं होता।

और अमरीका ऐसे देश है, जिनकी आबादी कम है और जिनके पास जमीन के विशाल क्षेत्र पड़े हैं। यहाँ भारत में मर्द और औरतो की तादाद बहुत ज्यादा है।

मैंने पिछले साल रवीन्द्रनाथ ठाकुर के कुछ भाषण पढ़े थे, जो उन्होंने बहुत समय पहले, सन् १९११ में दिये थे। उन्होंने बंगाल में सहकारी खेती अपनाने की जोरदार वकालत की थी। इसका कारण यह है कि बंगाल की परिस्थितियों में, जहाँ जमीन की छोटी बँटी हुई इकाइयाँ हैं, वहाँ सहकारी खेती के लिए गुजाइश है। वह राजनैतिक दृष्टिकोण नहीं था, आज की तरह उस समय उसके खिलाफ कोई विवाद खड़ा नहीं हुआ। वह मामूली तौर पर समझदारी-भरा दृष्टिकोण था और मेरा खयाल है कि उन्होंने अपने फार्म में उसे लागू किया। इसके बावजूद, पहला कदम सेवा सहकारी समितियों का है।<sup>१</sup>




---

१ नई दिल्ली में आयोजित राज्यों के सामुदायिक विकास और पंचायत राज मन्त्रियों के वार्षिक सम्मेलन में दिये गए भाषण के अंश।

